अवध की आवाज

www.avadhkaawaz.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

वर्ष–12 अंक–85 R.N.I.- UPHIN/2012/45127 लखनऊ शनिवार 27 जुलाई 2024 पृष्ठ – 4 मूल्य–3 रूपया

कारगिल युद्ध के दौरान जवानों के अदम्य शौर्य और साहस का लोहा दुनिया ने माना : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कारगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था। छद्म रूप से पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कर भारत पर युद्ध थोपने का कार्य किया था। किन्तु युद्ध का परिणाम क्या होगा, यह हमारे बहादुर जवानों ने तय किया। उस समय हमारी सेना के वीर जवानों के सामने विपरीत परिस्थितियां थीं, लेकिन हमारे उनके सामने कोई दुश्मन टिक नहीं पाया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय जवानों के अदम्य शौर्य और साहस का लोहा दुनिया ने माना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सेंट्रल कमांड, कैंट के सूर्या सभागार में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कारगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए कहा कि जिन वीर नारियों और परिवारों ने कारगिल युद्ध में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, आज उन्हें सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के अंदर भारत की पहचान जबरन एकाधिकार करने वाले देश की नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि बल, बुद्धि और विद्या में भारत जब दुनिया के अंदर सिरमौर था, तब भी हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। परंतु किसी आक्रांता ने यहां आकर हमारी शांति

और हमारी सद्भावना के हनन का दुस्साहस किया तो भारत माता के बहादुर जवानों ने मातृभूमि के रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि देश की सीमा की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों के साथ राज्य सरकार हमेशा खड़ी है। हमारा जवान किसी भी युद्ध या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है, तो राज्य सरकार की ओर उसके परिवार को आज 50 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। साथ ही उस परिवार के एक सदस्य की नौकरी की भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके अलावा 2017 से हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि शहीद होने वाले जवान की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए जिस गांव, नगर, कस्बे का वह जवान होगा, वहां पर एक भव्य स्मारक, इंस्टिट्यूट या किसी मार्ग का नामकरण उस जवान के नाम पर करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडेय के पिता, राइफलमैन सुनील जंग की माता, नायक आबिद खान की माता, नायक रामकेश चंद्र यादव की पत्नी, नायक राजेंद्र यादव की पत्नी, लांस नायक अशोक कुमार यादव के बेटे, ब्रिगेडियर अखिल कुमार सिन्हा, कर्नल प्रभात रंजन, कर्नल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कौशिक, कर्नल क्षितिज श्रीवास्तव, नायक जितेंद्र सिंह और सिपाही विनोद कुमार दुबे को सम्मानित किया। इससे पहले सीएम योगी सेंट्रल कमांड, कैंट में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित श्रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अमर जवानों को पुष्पचक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। साथ ही सीएम योगी ने कारगिल युद्ध के दौरान भारत के वीर जवानों के शौर्य को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

रेल बजट में अलीगढ़ को मिले 236.73 करोड़, नहीं मिला नाया प्रोजेक्ट, पुरानी योजनाओं में होगा निर्माण कार्य

अलीगढ़। भारत सरकार का रेल बजट जारी हो चुका है। इसके बाद रेलवे ने अपने बजट की पिंक बुक जारी कर दी है। इस बार के बजट में अलीगढ़ रेलवे को कोई नयी योजना नहीं मिली है। बल्कि पुरानी योजनाओं के तेजी से विकास के लिए ही बजट दिया गया है। अलीगढ़ रेलवे को इस बजट में 236.73 करोड़ रुपए मिले हैं। इससे अलीगढ़ में बिछ रही रेलवे की नई लाइनों और रेलवे के फ्लाई ओवर का काम तेजी से किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के सिटी साइड में यात्री पार्सल परिसर का विकास भी किया जाएगा। बजट में इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। अलीगढ़ में प्रोजेक्ट के लिए 236.73 करोड़ रुपए की राशि मौजूदा बजट में दिया गया। सबसे अधिक बजट हरदुआगंज फ्लाई ओवर, अलीगढ़ दाउद खां तीसरी लाइन, नए फ्लाइओवर को मिले हैं। अलीगढ़–हरदुआगंज फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके साथ ही अलीगढ़–दाउद खां तीसरी लाइन और नए फ्लाइओवर निर्माण के लिए भी 100–100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अलीगढ़ दाउद खां तीसरी लाइन और नया

फ्लाईओवर 6.90 किलोमीटर के होंगे। आलीगढ़–गाजियाबाद स्वचालित ब्लॉक और सिंगलिंग, अलीगढ़ जंक्शन पर दूसरी ब्लॉक रेक साइडिंग, सिडी साइडिंग माल शेड की शिफ्टिंग आदि को बजट जारी किया गया है। रेल बजट में अलीगढ़ जंक्शन को एक और लूप लाइन दी गई है। प्लेटफार्म नंबर एक से लूप लाइन निकाली जाएगी।जिसके लिए 4 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अप और डाउन ट्रैक बाधित होने पर लूप लाइन को इस्तेमाल करते हुए ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इससे ट्रेने प्रभावित न हो। अभी अलीगढ़ जंक्शन पर प्लेटफार्म नंबर दो ही लूप लाइन के रूप में काम कर रहा है। एक और लूप लाइन मिलने से काफी राहत मिलेगी। प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित सिंह ने बताया– पोस्टमॉर्टम हाउस और बदरपुर में बनी रेलवे की कालोनी पुरानी और जर्जर हो चुकी है। इसमें काफी आवासों को तोड़ा भी जा चुका है। इन आवासों की जगह अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए टाइप टू आवास स्थापित किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि यह आवास फ्लैट के रूप में विकसित किए जाएंगे। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया।

संक्षिप्त समाचार

एएमयू में ज्वार की फसल की नीलामी

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कार्यालय लैंड एंड गार्डन्स विभाग द्वारा ज्वार की फसल की नीलामी दिनांक 30 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे विभाग परिसर में होगी। इच्छुक व्यक्ति समय पर आकर बोली बोल सकते हैं। मेम्बर इंचार्ज प्रोफेसर जकी अनवर सिद्दीकी ने कहा है कि इच्छुक व्यक्ति फसल को नीलामी से पहले भली भांति देख लें बाद में किसी प्रकार का भ्रम मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व जमानत धनराशि एक घंटा पहले जमा करनी होगी। जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी उसकी जमानत राशि रोक ली जायेगी। जिन व्यक्तियों के नाम बोली नहीं छूटेगी उनकी जमानत राशि नीलाम कमेटी के आदेशानुसार वापस कर दी जायेगी। प्रो. सिद्दीकी ने कहा है कि नीलाम कमेटी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये सर्वोच्च बोली को स्वीकार करे या न करे या नीलामी को स्थगित करे। नीलाम का अंतिम फैसला नीलाम कमेटी में निहित होगा। किसी भी तरह का विवाद अलीगढ़ न्यायालय क्षेत्र तक सीमित होगा।

जान से मारने की धमकी देने का आरोप, पांच लोगों पर केस दर्ज

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर थाना क्षेत्र के पिपरसंड रोड के पास रहने वाले राजा सोनी ने सुजीत व उसके चार–पांच साथियों के खिलाफ थाने में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजा सोनी का कहना है कि रात करीब 11.45 बजे सुजीत और उसके चार–पांच साथी ऑटो रिक्शा लेकर उसके पास पहुंचे। सभी ने उसका कॉलर पकड़ा और लगभग आधा किलोमीटर तक ऑटो से खींचते हुए ले गए। इससे उसको काफी चोट लगी। आरोप लगाया है कि इस दौरान आरोपियों ने उसे इतना मारा कि बायां हाथ भी टूट गया। उसके बगल में मौजूद साले संदीप को भी गंभीर चोट आई है। राजा सोनी ने सभी आरोपियों के ऊपर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाते हुए सरोजनी नगर थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। सरोजनी नगर थाना प्रभारी शैलेन्द्र गिरी का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।

राजेश मीणा बने गृह सचिव

लखनऊ। एसपी बलिया पर गाज गिरने के बाद शासन ने राजधानी में पीएसी की 32वीं वाहिनी में तैनात विक्रांत वीर को बलिया का नया पुलिस कप्तान बनाया है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात विजय ढुल को यूपी 112 का एसपी बनाया गया है। 112 में तैनात एसपी दिनेश त्रिपाठी को कानपुर कमिश्नरेट में तैनात किया गया है। शुक्रवार को दो आईएएस के तबादले किए गए हैं। श्रीनिवास गुर्राला को पीडब्ल्यूडी में सचिव बनाया गया है। इसके अलावा राजेश मीणा गृह सचिव बनाए गए हैं। जबकि मयूर माहेश्वरी को लघु उद्योग निगम की जिम्मेदारी भी दी गई है।

अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को बताया मोहरा, कहा, वो हैं दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड

लखनऊ। सांसद और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर बड़ा हमला बोला है। सपा मुख्यालय पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में

उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं, और वो दिल्ली का मोहरा हैं। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गुजरे 10 वर्षों में भाजपा ने कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है। अखिलेश ने कहा कि मेरे पास ऐसी कई फाइलें हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सभी संस्थाओं और निगमों को समाप्त करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को धोखा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब हम विपक्ष में रहकर सवाल उठाते थे,तो प्रदेश सरकार हमको कहती थी कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। लेकिन जिस तरह हम सुन रहे हैं कि उनके अपने नेता विधायक ही कह रहे है कि उन्होंने अपने जीवन काल मे ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा, ये सोचने लायक है। अखिलेश ने कहा कि बलिया के मामले को सपा विधायक संग्राम सिंह विधानसभा में मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग जिनके पास सम्पर्क और पैसा है वो लोग लखनऊ के सरोजिनी नगर के मामले में खुलासा नहीं होने दे रहे हैं। इसी सरकार में एक आईपीएस कितने दिन फरार रहा,आप सब जानते है,फाइलें भरी पड़ी हैं। अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर व्यवस्था को समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नही कर सकती,मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे कई मित्र सेना में हैं। आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते है तो आप नौजवान को फौज की पक्की नौकरी क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने कहा संविधान में आरक्षण मूल भावना है, बीजेपी इसकी मूल भावना से छेड़छाड़ कर रही है। अपने ऊपर अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं। भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने से बचें, सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। केशव मौर्य ने लिखा–कमल खिला है खिलेगा,खिलता रहेगा।

प्रधान की शिकायत पर रुका शिक्षक का वेतन

अलीगढ़। अलीगढ़ में शिक्षकों की लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शिक्षक स्कूल ही नहीं जाते हैं और विद्यालय में ताला लगा रहता है। जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। ऐसे ही एक मामले में लापरवाही करने वाले शिक्षक का वेतन रोका गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस मामले की शिकायत मिली थी। जिसके बाद उन्होंने मामले की जांच ब्लाक शिक्षा अधिकारी को सौंपी। बीईओ की रिपोर्ट आने के बाद बीएसए डॉ राकेश सिंह ने आरोपी शिक्षक का वेतन रोक दिया है और उन्हें तत्काल स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। बिजौली ब्लाक के दीनापुर गांव की प्रधान मुन्नी देवी ने जिलाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके गांव में बेसिक स्कूल है। गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय दीनापुर में दो शिक्षक कमलकांत शर्मा और प्रशांत शर्मा की तैनाती है। सहायक अध्यापक कमलकांत शर्मा वर्तमान में बीमार होने के कारण मेडिकल लीव पर चल रहे हैं। वहीं दूसरे सहायक अध्यापक प्रशांत कुमार शर्मा स्कूल आते ही नहीं हैं। प्रशांत लंबे समय से विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं। इस शिकायत के बाद बीएसए ने मामले की जांच कराई थी। बिजौली ब्लाक के उच्च प्राथमिक विद्यालय दीनापुर में इस समय 40 से ज्यादा विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं, जो रोज स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले लगभग 15 दिन से ज्यादा समय से स्कूल बंद चल रहा है। प्रधान ने बताया कि एक शिक्षक स्कूल आते ही नहीं हैं। लेकिन दूसरे शिक्षक स्कूल आते थे तो बच्चों की पढ़ाई चलती रहती थी। उनके बीमार होने के बाद स्कूल ही बंद हो गया। बीएसए डॉ राकेश सिंह ने बताया कि प्रधान की शिकायत पर बीईओ से मामले की जांच कराई गई थी। जिसमें सहायक अध्यापक प्रशांत कुमार शर्मा दोषी मिले हैं। जिसके बाद उनका वेतन रोक दिया गया है। मामले की विस्तृत जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तकरोही में डायरिया के 35 मरीज मिले, स्वास्थ विभाग ने लगाया कैंप, 1580 लोगों का किया चेकअप

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में डायरिया का कहर जानलेवा बन चुका है। इंदिरा नगर के तकरोही इलाके में 2 लोगों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग एक्टिव है। शुक्रवार को सुबह से मेडिकल, नगर निगम और जलकल की टीम प्रभावित इलाके पहुंची। यहां 2 दर्जन से ज्यादा लोग उल्टी–दस्त से बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कैंप लगाकर इलाके में दवा बांटी जा रही है। शुक्रवार को दोबारा जलकल की टीम ने पानी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। इससे पहले गुरुवार को सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। नगर निगम की टीम भी साफ–सफाई के साथ गंदगी हटाने के लिए पहुंची है। राजधानी में इससे पहले कल्ली पश्चिम, गजरियन खेड़ा, फैजुल्लागंज और नौबस्ता के बाद तकरोही में डायरिया का अटैक सामने आया है। यहां की मायावती कॉलोनी की 12 साल की छात्रा कायनात को उल्टी, दस्त की शिकायत पर परिवारीजनों ने लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया था। मंगलवार देर शाम उसकी मौत हो गई थी। इसी दिन 55 साल की महिला की भी डायरिया से मौत की खबर है। महिला को पहले बाराबंकी के सूर्या अस्पताल में भर्ती किया गया था। बाद में गंभीर हालत में वहां से लखनऊ के लिए रिफर कर दिया। मंगलवार देर शाम अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। सीएमओ ऑफिस के प्रवक्ता योगेश रघुवंशी के मुताबिक लखनऊ के तकरोही और नौबस्ता दोनों जगह मेडिकल टीम कैंप कर रही है। इंदिरा नगर सीएचसी की मेडिकल टीम लगी तकरोही में अब तक कुल 345 घरों का होम सर्विलांस किया जा चुका है। इस दौरान कुल 1580 लोगों तक मेडिकल टीम ने पहुंच कर उनका हालचाल जाना। कुछ लोगों में डायरिया की शिकायत है। इसके अलावा ज्यादातर लोगों में उल्टी दस्त के मामूली लक्षण हैं। सभी को घर पर ही दवाई मुहैया कराई जा रही है। गंभीर लोगों को बिना देर किए अस्पताल में भर्ती कराए जाने के भी निर्देश हैं। हालात नियंत्रण में हैं, पैनिक जैसे कोई हालात नहीं हैं।

बलरामपुर चिकित्सालय में रक्त दान शिविर का आयोजन

मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं : डा. पवन कुमार

लखनऊ। ऑल इंडिया पयाम ए इंसानियत फोरम लखनऊ की तरफ बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ की ओ0पी0डी0 में एक रक्त दान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान मदरसा नदवा तुल उलेमा के 50 छात्रों ने समाज और मानवता के लिए रक्त दान किया। इस रक्त दान शिविर में डॉ0 पवन कुमार अरुण डायरेक्टर बलरामपुर चिकित्सालय, डॉ0 एन0 बी0 सिंह मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और संस्था के सम्मानित सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर डायरेक्टर बलरामपुर चिकित्सालय डा0 पवन कुमार अरुण ने संस्था का उनके इस काम के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि रक्त दान करना जितने पुण्य का काम है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता,इन छात्रों ने जो रक्त दान किया है उनका ये कार्य मानवता की मिसाल है। आज पूरे देश में लोग जाति और धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हैं लेकिन रक्तदान से पीछे रहते हैं वहीं मदरसा नदवा तुल उलेमा के इन छात्रों ने जो रक्तदान किया है वो किसी न किसी जान बचाएगा और वो भी बिना जात और धर्म देखे। मेरा आशीर्वाद है कि इन छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, और ये छात्र हमारे देश को और बुलंदी तक ले कर जाएं। हमारे देश में हर साल न जाने कितने ही लोग सिर्फ समय पर रक्त न मिल पाने की वजह से अपनी जान गँवा बैठते हैं ,और ये ऐसी चीज है जिसे किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता है। हमें सोचना चाहिए कि दुनिया के हर धर्म से बड़ा मानवता का धर्म है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा0 एन0 बी0 सिंह ने कहा कि इन छात्रों ने रक्त दान कर के मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा किया है। आज हमारे समाज में इस तरह के काम बहुत कम हो गये हैं। आज हमें लोगों को रक्त दान के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है क्या पता आपके द्वारा दान किया गया रक्त आप के ही किसी अपने के काम आ जाये। ऐसे में संस्था का ये काम सराहनीय है । मदरसा नदवा तुल उलेमा के इन छात्रों का भी एक मात्र उद्देश्य मानवता की सेवा ही करना है। बाद में संस्था के कोऑर्डिनेटर शफीक चौधरी ने सब के सहयोग की प्रशंसा की और तमाम लोगों का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। इस दौरान डॉ0 विनोद, डॉ0 उस्मानी के साथ संस्था के सदस्य गण मौजूद रहे।

2017 के फार्मूले से ही सपा का हराया जा सकेगा : केशव

योगी से मिलने के बाद डिप्टी सीएम से मिले विधायक

चर्चा का विषय बनी बीजेपी की आंतरिक कलह

लखनऊ। बीजेपी लीडर और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी विधायकों को खास संदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद विधायकों ने केशव से मुलाकात की। केशव ने विधायकों से कहा कि 2017 के फॉर्मूले से ही 2027 में सपा को हराया जा सकता है।उन्होंने विधायकों से कहा,2017 के मुताबिक ही सोशल इंजीनियरिंग करने और समाज के दबे कुचले वर्गों को प्रतिनिधित्व देने व उनकी बात सुनने को कहा। इस समय बीजेपी की तथाकथित आंतरिक कलह चर्चा का विषय बनी हुई है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तथाकथित तकरार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं।यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है। सीएम योगी समीक्षा बैठक कर रहे हैं लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन बैठकों में शामिल नहीं हो रहे है।माना जा रहा है कि यूपी में सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सबकुछ सही नहीं चल रहा है। अभी तक किसी भी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने हाल में ही बयान दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और उनके इस बयान से ही यूपी सियासत तेज हुई थी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बीच मची कलह के बीच सपा मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुर्सी की लड़ाई में जनता काफी परेशान है।अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा,भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में, उप्र में शासन–प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है।तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है. जनता के बारे में सोचनेवाला भाजपा में कोई नहीं है।

सम्पादकीय

अर्थव्यवस्था को तीव्र गति एवं महाशक्ति बनाने वाला बजट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का प्रथम सम्पूर्ण बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, उनकी ओर से प्रस्तुत यह बजट एक मौलिक सोच एवं दृष्टि से दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित करने एवं सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिये आगे की राह दिखाने वाला है। संभावना है कि इस बजट में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, नौकरीपेशा का थोड़ी राहत, बुनियादी ढांचे में निवेश, पर्यटन को बढ़ावा, आदिवासी उन्नयन, क्षमता विस्तार, हरित एवं कृषि विकास, महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी, मोदी के नये भारत–सशक्त भारत–विकसित पर बल दिया गया है। वित्त मंत्री ने सरकार की 9 प्राथमिकताओं –खेती में उत्पादकता और मजबूती बढ़ाना, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, मानव संसाधन का समावेशी विकास और सामाजिक न्याय, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्नोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स का ऐलान किया है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की रफ्तार को भी गति देगा। बजट में जहां बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है वहीं महंगाई को नियंत्रित करने की मंशा साफ दिखाई दी है। विकास, स्टार्टअप और रोजगार सृजन के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट देश को न केवल विकसित देशों में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरे स्थान दिलाने के संकल्प को बल देने में सहायक बनेगा। सातवीं बार बजट प्रस्तुत कर वित्तमंत्री सीमारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में पांच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था।

सशक्त एवं विकसित भारत निर्मित करने, उसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने और अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में प्रस्तुत आम बजट इसलिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि मोदी सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया, न कि लोकलुभावन योजनाओं के जरिये प्रशंसा पाने अथवा कोई राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। राजनीतिक हितों से ज्यादा देशहित को सामने रखने की यह पहल अनूठी है, प्रेरक है। अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो इस बजट से पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इस बजट में मध्यम वर्ग को लम्बे अन्तराल के बाद 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई करने वालों को बड़ी राहत दी है। नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। साथ ही नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में भी कुछ अहम बदलाव करने का एलान किया है। मौजूदा नियमों के तहत एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस लिमिट को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की घोषणा की। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा। मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय घाटा 2024–25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। लक्ष्य घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे पहुंचाने का लक्ष्य है। 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति देने की दृष्टि से यह बजट कारगर साबित होगा, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, रोजगार के नये अवसर सामने आयेंगे, उत्पाद एवं विकास को तीव्र गति मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक क्षेत्र में काफी उतार–चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन इन सब स्थितियों के बावजूद इस बजट प्रावधानों के माध्यम से देश को स्थिरता की तरफ ले जाते दिखाई पड़ रहे हैं। बजट हर वर्ष आता है। अनेक विचारधाराओं वाले वित्तमंत्रियों ने विगत में कई बजट प्रस्तुत किए। पर हर बजट लोगों की मुसीबतें बढ़ाकर ही जाता रहा है। लेकिन इस बार बजट ने अर्थव्यवस्था में नयी परम्परा के साथ राहत की सांसें दी है तो नया भारत– सशक्त भारत–विकसित के निर्माण का संकल्प भी व्यक्त किया है। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रेलों का विकास, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के विकास के साथ–साथ किसानों, आदिवासियों, गांवों और गरीबों को ज्यादा तवज्जो दी गयी है। सच्चाई यही है कि जब तक जमीनी विकास नहीं होगा, तब तक आर्थिक विकास की गति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। इस बार के बजट से हर किसी ने काफी उम्मीदें लगा रखी थीं और उन उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है। विशेषतः नौकरीपेशा लोगों ने राहत की सांस ली है।

संभवतः इस बजट को नया भारत निर्मित करने की दिशा में लोक–कल्याणकारी बजट कह सकते हैं। यह बजट वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की दिशाओं को भी उद्घाटित करता है। आम बजट न केवल आम आदमी के सपने को साकार करने, आमजन की आकांक्षाओं को आकार देने और देशवासियों की आशाओं को पूर्ण करने वाला है बल्कि यह देश को समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण एवं दूरगामी सोच से जुड़ा कदम है। बजट के सभी प्रावधानों एवं प्रस्तावों में जहां 'हर हाथ को काम' का संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से उजागर हो रहा है। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत यह बजट निश्चित ही अमृत बजट है। जिसमें भारत के आगामी 25 वर्षो के समग्र एवं बहुमुखी विकास को ध्यान में रखा गया है। बीते कुछ सालों में नरेन्द्र मोदी ने इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है।

आदिवासी समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। बजट में टूरिज्म पर विशेष बल दिया गया है। पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है।. भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के सरकार के प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। सरकार ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगी, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आशा के अनुरूप ही बजट का फोकस किसानों, आदिवासियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, रोजगार, युवाओं की अपेक्षाओं, विकास और ग्रामीण क्षेत्र एवं पर्यटन पर रखा है। अपने ढांचे में यह पूरे देश का बजट है, एक आदर्श बजट है। इसका ज्यादा जोर सामाजिक विकास पर है। अक्सर बजट में राजनीति, वोटनीति तथा अपनी व अपनी सरकार की छवि–वृद्धि करने के प्रयास ही अधिक दिखाई देते है लेकिन बावजूद यह बजट राजनीति प्रेरित नहीं, देश प्रेरित है। इस बजट में जो नयी दिशाएं उद्घाटित हुई है और संतुलित विकास, भ्रष्टाचार उन्मूलन, वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शी शासन व्यवस्था का जो संकेत दिया गया है, सरकार को इन क्षेत्रों में अनुकूल नतीजे हासिल करने पर खासी मेहनत करनी होगी।

रजिया सुल्तान से राबड़ी देवी तक एक जैसी कहानी

अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरे सदन में राजद विधायक रेखा देवी के लिए ऐसा कहा। इससे पहले कल नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के सांसद ललन सिंह ने राबड़ी देवी के बारे में कहा कि उन्हें हस्ताक्षर करना तो ढंग से आता नहीं, वो बजट क्या समझेंगी। दिल्ली सल्तनत पर 1236 से 1240 के बीच शासन करने वाली रजिया सुल्तान के लिए कहा जाता था कि उनमें सारी खूबियां थीं, सिवाए एक के, कि वह महिला थी। हिंदुस्तान 1236 से 2024 में आ गया, लेकिन महिलाओं के लिए हिकारत भरी सोच अब भी वैसी ही है। क्या फर्क पड़ता है कि इस देश में एक महिला प्रधानमंत्री हो चुकी हैं, अभी एक महिला राष्ट्रपति हैं, इससे पहले भी एक महिला राष्ट्रपति हो चुकी हैं। अंतरिक्ष से लेकर सेना, पुलिस, चिकित्सा, न्याय क्षेत्र, पत्रकारिता, उद्योग हर जगह महिलाएं अपनी काबिलियत का लोहा मनवाती रही हैं। लेकिन इस बात का हवाला देकर यह कहना कि देश में महिला सशक्तिकरण हो रहा है और महिलाओं को अब बराबरी का दर्जा मिलने लगा है, खुद को छलावे में रखने से अधिक और कुछ नहीं है। अगर महिलाएं अपने लिए बनाए दायरों से निकल कर बाहर आ रही हैं और उनके लिए असंभव, अछूते समझे जाने वाले क्षेत्रों में भी काम कर रही हैं, तो इसके पीछे या तो उनकी कोई मजबूरी होती है या परिवार का अभूतपूर्व सहयोग और प्रगतिशील सोच का असर होता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि देश में महिलाओं के लिए सोच बदल चुकी है। मानसिकता में अब भी लैंगिक भेदभाव कूट–कूट कर भरा हुआ है, जिसके उदाहरण उपरोक्त बयानों से समझे जा सकते हैं। देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सात बार बजट पेश करके रिकार्ड बना लिया है। उनके बजट का सटीक और तार्किक विश्लेषण करने वालों में कई महिलाएं भी शामिल होंगी, जिन्हें अर्थशास्त्र की गहरी समझ होगी। लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि राबड़ी देवी को इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ललन सिंह के हिसाब से उन्हें हस्ताक्षर करने ठीक से नहीं आते तो वे बजट पर भी नहीं बोल सकती। क्या ललन सिंह नरेन्द्र मोदी के बारे में भी ऐसी ही बात कह सकते हैं, क्योंकि श्री मोदी हस्ताक्षर अच्छे से कर लें, लेकिन अर्थशास्त्र के ज्ञाता तो वे नहीं हैं। उनकी डिग्री भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की है, अर्थशास्त्र की नहीं है। फिर भी वे शिक्षकों से लेकर वैज्ञानिकों, बुनकरों से लेकर उद्योगपतियों सबको समझाइश देते रहते हैं। राबड़ी देवी को और देश के तमाम नागरिकों को बजट पर बोलने का उतना ही हक है जितना ललन सिंह या नरेन्द्र मोदी को है। क्योंकि बजट देश के आम नागरिकों के लिए बनता है और उनके ही धन से बनता है, इसलिए अपने विचार रखने का अधिकार भी है। ललन सिंह को अगर राबड़ी देवी के विचारों को खारिज करना ही था तो अपने तर्क सामने रखते। लेकिन उनका पौरुषवादी अहंकार यहां आड़े आ गया कि एक महिला, जो उनके हिसाब से पर्याप्त शिक्षित भी नहीं है और ऊपर से पूर्व मुख्यमंत्री, चार बार की विधायक और विधानपरिषद की सदस्य हैं, वो कैसे बजट पर अपनी राय दे सकती हैं। कुछ ऐसी ही तकलीफ नीतीश कुमार को भी हो गई, जब राजद विधायक रेखा देवी को उन्होंने केवल इसलिए चुप कराना चाहा, क्योंकि वे एक महिला हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पर रेखा देवी अपनी बात रख रही थीं और नीतीश कुमार को बोलने नहीं दे रही थीं, तो गुस्से में आकर नीतीश कुमार ने कहा कि बोल रही हो, फालतू बात। इन लोगों ने किसी महिला को आगे बढ़ाया है क्या? पांचवीं के बाद मैंने महिलाओं को पढ़ाया है। इसलिए कह रहे हैं, चुपचाप सुनो। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को भूल गए कि रेखा देवी को मसौढ़ी की जनता ने विधानसभा में इसलिए नहीं भेजा कि वो चुपचाप सरकार की बात सुनती रहें, बल्कि जनता की ओर से आवाज उठाएं इसलिए भेजा है। नीतीश कुमार यहां महिला होने के नाम पर रेखा देवी को चुप कराने लगे और ये भूल गए कि वे खुद जनता की आवाज दबा रहे हैं। अगर जदयू अभी इंडिया गठबंधन का साथी होता तो राष्ट्रीय महिला आयोग के स्वतरू संज्ञान लिए नोटिस नीतीश कुमार और ललन सिंह को पहुंच जाते। लेकिन जदयू के कारण भाजपा की सरकार सत्ता में बनी हुई है, तो एक तरह से जदयू को भी महिलाओं के अपमान की खुली छूट मिल ही गई है। याद कीजिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वाणी और विचार महिलाओं के लिए किस तरह के रहे हैं। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की मुंबई की रैली में शक्ति शब्द का जिक्र भाजपा को घेरने के लिए किया तो नरेन्द्र मोदी ने इसे मातृ शक्ति से जोड़ कर कहा कि मैं आखिरी सांस तक शक्ति के सम्मान के लिए लडूंगा। लेकिन इसी चुनाव में मंगलसूत्र बेचने से लेकर विपक्षी दलों के मुजरा करने की बात कहकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी नजर में महिलाओं का ओहदा क्या है। सोनिया गांधी के लिए श्री मोदी कांग्रेस की विधवा और सुनंदा पुष्कर के लिए पचास लाख की गर्लफ्रेंड जैसी ओछी टिप्पणी कर ही चुके हैं। प.बंगाल जाकर संदेशखोली की महिलाओं के दर्द का जिक्र करने वाले नरेंद्र मोदी आज तक मणिपुर नहीं गए, न ही वहां की पीड़ित महिलाओं की कोई सुध उन्होंने ली। महिला पहलवानों को भी उन्होंने उनके हाल पर छोड़ दिया है कि वे अपने इंसाफ की लड़ाई खुद लड़ें। दरअसल नरेन्द्र मोदी, नीतीश कुमार, ललन सिंह ये केवल चेहरा और नाम हैं, इनके बयानों और विचारों में समाज की असलियत का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जिसमें ऊपरी तौर पर बात महिला बराबरी और सम्मान की होती है, लेकिन भीतर ही भीतर एक सड़ी–गली सोच पसरी हुई है, जिसमें महिला को किसी भी हद तक जाकर प्रताड़ित किया जा सकता है। फिर चाहे वह सरेआम निर्वस्त्र कर के जुलूस निकालना हो या जिंदा गाड़ना हो। सलीम–अनारकली की काल्पनिक कहानी में यह बताया गया है कि शहंशाह अकबर ने हुकूमत की खातिर अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। फिल्म मुगले आजम में इसका प्रभावशाली चित्रण है, फिल्म में दिखाया गया है कि दीवार के दूसरी ओर से अनारकली को निकाल लिया जाता है, यानी यहां अकबर का उदार रूप दिखा दिया गया। फिल्म है, तो उसमें कल्पनाओं का खेल किया जा सकता है। लेकिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने शासन में दो महिलाओं को जिंदा दफनाने की कोशिश पर क्या कहेंगे, किस तरह अपना उदारवादी चेहरा, लाड़ली बहनों के काबिल भाई का चेहरा प्रस्तुत कर पाएंगे। रीवा जिले में ममता और आशा पांडेय नाम की दो महिलाओं को जमीन विवाद के कारण दबंगों ने जमीन में जिंदा दफना ही दिया था, क्योंकि इन दोनों देवरानी–जेठानी ने उनकी जमीन से होकर गुजरने वाली सड़क का विरोध किया। घर में कोई पुरुष मौजूद नहीं था और इन दोनों ने विरोध करने का साहस दिखाया तो पुरुषों ने भी अपनी ताकत दोनों को जमीन में गाड़ने में दिखा दी। इस घटना का वीडियो बना और वायरल हुआ तो उन दोनों की जान बचाई गई और अभी उनका इलाज चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासन में आदिवासी के सिर पर पेशाब करने का शर्मनाक कृत्य सामने आया था तो अपनी छवि बचाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने उस आदिवासी को घर बुलाकर उसके पैर धोए। अब मोहन यादव की बारी छवि बचाने की है। क्या इस रक्षा बंधन पर इन दोनों महिलाओं से मुख्यमंत्री राखी बंधवाएंगे और उन्हें रक्षा का वचन देंगे, ये देखना होगा।

राजनैतिक हथियार बनता केन्द्रीय बजट

केजरीवाल के खिलाफ मुकदमों के नतीजे पर टिका आप का राजनीतिक भविष्य2024 के लोकसभा चुनाव में महिला मतदाता निभायेंगी बुधवार को लोकसभा में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2024–25 का बजट जहां एक ओर देश के मुठ्टी भर लोगों को खुशी और ज्यादातर वर्गों के लिये निराशा लेकर आया है, वैसे ही गिनती के राज्यों को खुश करने वाला जबकि अधिकतर को नाखुश करने वाला साबित हुआ है। सरकार बनाने में मददगार रहे दो राज्यों– बिहार और आंध्रप्रदेश की झोलियों को जिस तरह से केन्द्र सरकार ने भरा है, उससे अनेक राज्यों का मायूस होना स्वाभाविक है। इस बजट में जिस प्रकार से सरकार ने भेदभाव बरता है उससे राज्यों में फूट पड़ने की आशंका हैय और उसका सबसे बुरा पहलू यह है कि वह देश की संघीय व्यवस्था पर गहरी चोट है। पिछले 10 वर्षों से देश पर शासन कर रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मुख्य सिपहसालार केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अनेक कृत्यों से जिस तरह भारत के संघीय ढांचे की नींव को हिलाकर रख दिया है, उसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में इस बजट को देखा जाना चाहिये। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यदि बजट का इस्तेमाल कर राज्यों का राजनैतिक समर्थन जुटाने की परम्परा चल पड़ी तो केन्द्रीय राजस्व का बंटवारा अलग–अलग राज्यों की जरूरतों के आधार पर नहीं बल्कि सियासी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किया जाने लगेगा। यह व्यवस्था वंचित रह गये राज्यों में असंतोष को जन्म देगा। उल्लेखनीय है कि आंध्रप्रदेश की तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) के 16 और बिहार की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के 12 सांसदों (लोकसभा सदस्य) के बल पर मोदी सरकार टिकी हुई है। पहले से ही अंदेशा था कि अपने समर्थन के एवज में इन दोनों ही पार्टियों के नेता, क्रमशरू चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार (अपने–अपने राज्यों के मुख्यमंत्री) केंद्र की बांहें मरोड़कर कीमत वसूल करेंगे। इन दोनों नेताओं की अपने–अपने प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग रही है। मांग तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की भी थी लेकिन वहां अब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन गयी है इसलिये वह मसला कम से कम वहां तो खत्म हो गया है। इस बजट में टीडीपी और जेडीयू के प्रति केन्द्र का खास अनुराग झलका है। चंद्रबाबू नायडू ने जिस विशेष राज्य का दर्जा न मिलने के कारण 2018 में भाजपा का साथ छोड़कर नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस को टा–टा कर दिया था, इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में फिर से उसका दामन थामा था। तभी से नायडू की मांग थी कि आंध्रप्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य के बन जाने से उन्हें अपनी राजधानी बनाने की जरूरत है। इसके लिये 15000 करोड़ रुपये उन्हें दिये गये। उनका खुश होना स्वाभाविक है। दूसरी खुशी नीतीश बाबू को मिली है। चुनाव के ऐन पहले विपक्षी गठबन्धन इंडिया को छोड़कर एनडीए में 17 महीने बाद वापसी करने वाले नीतीश कुमार को भी पुरस्कार मिला है– 59 हजार करोड़ रुपए का। इसका बड़ा हिस्सा बिहार में आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण करने सम्बन्धी उपायों पर खर्च होंगे। हालांकि इसकी हवा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (सांसद) ने यह कहकर निकाल दी है कि जब तक नेपाल और उप्र से बिहार को जाने वाली नदियों की बाढ़ को नियंत्रित नहीं किया जाता, तब तक बिहार की नदियों की बाढ़ को नियंत्रित कर पाना असम्भव है। जिस तरह से चंद्रबाबू अब विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की बात भूल गये हैं, वैसे ही नीतीश कुमार भी इससे इतने गदगद हैं कि वे पत्रकारों से कह रहे हैं कि, श्वे तो पहले से कह रहे थे कि उन्हें या तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज।केन्द्र ने यह राशि तो दे ही दी है। हालांकि वे भूल रहे हैं कि इससे बड़ी राशि का ऐलान तो मोदी राज्य की अपनी प्रचार सभाओं में करते रहे थे। बहरहाल, यह भी सच है कि यह राशि राज्य द्वारा केन्द्र की देखरेख और निर्देश पर ही खर्च करनी होगी। जो भी हो, यह आवंटन नीतीश को अपना चेहरा छिपाने और इंडिया छोड़कर एनडीए में शामिल होने के फैसले को सही ठहराने के लिये काफी है। केन्द्रीय बजट एक साझा सम्पत्ति होती है जिसके जरिये पूंजी का वितरण भेदभाव से रहित होना चाहिये। उसका पैमाना इस आधार पर नहीं होना चाहिये कि कौन से राज्यों में अपनी पार्टी की सरकार है या सहयोगी दलों की है या फिर विरोधी दलों की है अथवा किससे समर्थन मिलेगा या किससे नहीं मिलेगा। सेन्ट्रल पूल का पैसा अलग–अलग राज्यों से आता है और वह पूरे देश के सम्मिलित पुरुषार्थ का परिणाम होता है। राज्यों की जरूरतों के आधार पर वह राज्यों को दिया जाता है। इस पक्षपात से न केवल विरोधी पार्टी की सरकारों वाले प्रदेशों में असंतोष फैलेगा बल्कि केन्द्र के साथ उनकी एकजुटता में भी कमी आयेगी। यह देश की एकता के लिये घातक होगा। इस भेदभावपूर्ण बजट की पहली प्रतिक्रियास्वरूप यह सामने आया है कि 27 जुलाई को आयोजित नीति आयोग की बैठक का चार राज्यों ने बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है।तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, तेलंगाना के. रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सिद्धारमैया और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक में नहीं जायेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी जायेंगी लेकिन वे सवाल पूछने की तैयारी से जा रही हैं। बजट से राजनैतिक हितों को साधने का खेल संघवाद और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह इसलिये बहुत घातक है कि यदि इसे परम्परा बना दिया गया तो बजट एक राजनैतिक हथियार बन जायेगा।

केन्द्रीय बजट 2024–25 में राष्ट्रीय संसाधनों का जबरदस्त दुरुपयोग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपने बजट पटल बड़े आत्मविश्वास के साथ आईं, जो यह एक प्रतीकात्मक इशारा था कि वह वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एक परिवर्तनकारी संघीय बजट के रूप में लोगों द्वारा प्रत्याशित प्रावधानों के साथ आई हैं। फिर भी, 23 जुलाई को राष्ट्र के सामने जो कुछ सामने आया, वह कोई पारंपरिक आर्थिक खाका नहीं था, बल्कि एक नाजुक गठबंधन बजट था, जिसे अलग–अलग राजनीतिक गठबंधनों को खुश करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था।

अल्पमत के जनादेश के साथ शासन करने की अनिवार्यताओं को दर्शाते हुए एक रणनीतिक पैंतरेबाजी में सीतारमण ने एक ऐसा दस्तावेज पेश किया जिसे राजनीतिक बजट कहा जा सकता है, एक ऐसा दस्तावेज जो आर्थिक प्रबंधन की पारंपरिक अनिवार्यताओं की तुलना में गठबंधन राजनीति की अनिवार्यताओं के लिए अधिक अनुकूल है। फिर सबसे दुखद बात यह कि उन्हें इस बात पर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई कि उनके खेल कौशल को बजट बनाने के अन्यथा गंभीर कार्य के लिए स्पष्ट विचलन के रूप में देखा जायेगा।

बिहार और आंध्र प्रदेश की क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा समर्थित अल्पमत भाजपा सरकार की पृष्ठभूमि के आलोक में बजट की रूपरेखा में समझौते और समायोजन के अमिट निशान थे, जहां संख्याएं अक्सर सिद्धांतों या विवेक से अधिक नीति निर्धारित करती हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अपेक्षित उपायों की चूक ने व्यापक आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाले बिना क्षेत्रीय सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक नाजुक संतुलन को रेखांकित किया– एक चतुर आर्थिक जाल–बट्टा, जो समकालीन भारत में गठबंधन शासन की पेचीदगियों को दर्शाता है। सीतारमण के संबोधन का मुख्यबिंदु रोजगार सृजन पर जोर था, जो एक चिरस्थायी चिंता रही है, जो आर्थिक झटकों से और बढ़ गई है। भाजपा की चुनावी असफलताओं के बाद पार्टी के चुनाव–पश्चात विचार–विमर्श में यह तथ्य सामने आया। फिर भी, सरकार की रोजगार सृजन के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता के बावजूद ठोस, लक्ष्य–विशिष्ट प्रस्तावों की अनुपस्थिति स्पष्ट थी। रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत रोडमैप की अनुपस्थिति और अल्प–रोजगार और बेरोजगारी से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए बुलंद बयानबाजी को मूर्त परिणामों में बदलने में सक्षम ठोस उपायों की कमी इतनी स्पष्ट थी कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। बजट का विशुद्ध रूप से आर्थिक गणना के बजाय राजनीतिक गणना की ओर झुकाव क्षेत्रीय भागीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई राजकोषीय प्राथमिकताओं के परस्पर क्रिया द्वारा रेखांकित किया गया था। सत्ता पर भाजपा की कमजोर पकड़ के लिए महत्वपूर्ण नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बजटीय विचार–विमर्श में प्रमुखता से उभरे, उनकी रणनीतिक अनिवार्यताएं अक्सर आर्थिक विवेक की सार्वभौमिक मांगों पर भारी पड़ीं। संसाधन आवंटन की रूपरेखा इन क्षेत्रीय क्षत्रपों की छाप को दर्शाती है, जो कि अनियंत्रित आर्थिक प्रबंधन के आदर्शवाद पर गठबंधन शासन की व्यावहारिक आवश्यकताओं के भारी पड़ने को सामने रखती है। समावेशी विकास के प्रति सीतारमण के प्रस्ताव राजनीतिक सुविधा की अनिवार्यताओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, फिर भी इस कथित प्रतिबद्धता को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित विरोधाभासों को सामने लाते हैं। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ठोस उपायों की अनुपस्थिति– जो कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे आम आदमी के लिए एक मुख्य डर है– राजनीति और अर्थशास्त्र के बीच असंगत तालमेल को ही रेखांकित करती है। इसने अल्पकालिक राजनीतिक अनिवार्यताओं और स्थायी आर्थिक प्रबंधन की मांगों के बीच तनाव को उजागर किया– एक विसंगति जिसने राजकोषीय विवेक के मामलों में सरकार की व्यापक विश्वसनीयता को कमजोर करने के साथ–साथ केंद्रीय बजट के निर्माण में संवैधानिक औचित्य के निर्देशों को कमजोर करने का खतरा उत्पन्न कर दिया है।

निर्मला सीतारमण का 2024–25 का बजट आलोचना और निराशा का तूफान खड़ा करने के लिए बाध्य है, खासकर उन राज्यों से जो पारंपरिक रूप से सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ मतभेद रखते हैं। भारत के बजटीय आवंटनों में आमतौर पर निहित संघवादी लोकाचार से हटकर, उनका राजकोषीय खाका संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को बाधित करता हुआ दिखाई दिया, जिससे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे विपक्ष शासित राज्यों को महत्वपूर्ण आवंटनों से स्पष्ट रूप से वंचित रहना पड़ा। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के लिए किसी भी सार्थक स्वीकृति या आवंटन की अनुपस्थिति ने भारत के संवैधानिक ढांचे में निहित संघवादी सिद्धांतों से एक स्पष्ट प्रस्थान को रेखांकित किया। ऐतिहासिक रूप से, भारत की बजटीय प्रक्रिया ने सहकारी संघवाद के सिद्धांत का पालन करते हुए, राजनीतिक संबद्धता के बावजूद, विभिन्न राज्यों की राजकोषीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को संतुलित करने का प्रयास किया है। हालांकि, सीतारमण की बजटीय रणनीति गठबंधन सहयोगियों को खुश करने की ओर निर्णायक रूप से झुकी हुई दिखाई दी। विपक्ष शासित राज्यों के लिए, बजट का हाशिए पर होना केवल राजकोषीय उपेक्षा से कहीं अधिक था। यह एक प्रणालीगत ढंग से वंचित करने और संघीय ढांचे की विशेषता वाली विविधा आर्थिक अनिवार्यताओं के प्रति उपेक्षा का प्रतीक था। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य, जो अपने मजबूत आर्थिक योगदान और विशिष्ट विकासात्मक चुनौतियों के लिए जाने जाते थे, खुद को हाशिये पर पाते हैं। राजकोषीय चर्चा में, उनकी तत्काल जरूरतें गठबंधन राजनीति की अनिवार्यताओं के सामने दब गईं।

सामाजिक कल्याण और मानव विकास सूचकांकों पर जोर देने के लिए मशहूर केरल में बजट की उपेक्षा ने गहरी छाप छोड़ी। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए लक्षित आवंटन की अनुपस्थिति ने केंद्र की राजकोषीय प्राथमिकताओं और जमीनी हकीकतों के बीच एक अलगाव को रेखांकित किया। पर्यटन और प्रेषण जैसे क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भर अर्थव्यवस्था के साथ, केरल को पर्याप्त बजटीय प्रावधानों से बाहर रखा जाना उभरती वैश्विक चुनौतियों के सामने लचीलापन बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के एक चूके हुए अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह, तमिलनाडु ने भी अपने दुर्जेय औद्योगिक आधार और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान के साथ–खुद को हाशिए पर पाया। राज्य की विकास संबंधी आकांक्षाएं, विशेष रूप से विनिर्माण, कृषि और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में, कहीं और राजनीतिक समायोजन की जरूरतों के कारण हाशिए पर चली गईं। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और कृषि लचीलापन बढ़ाने के लिए लक्षित निवेश की कमी ने एक अदूरदर्शी राजकोषीय दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसने दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर अल्पकालिक राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी। कर्नाटक, एक अन्य राज्य जो एक विपक्षी दल द्वारा शासित है, में असंतोष की प्रतिध्वनियां स्पष्ट थीं। एक प्रमुख आर्थिक केंद्र और तकनीकी महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद, बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल नवाचार और सतत शहरीकरण के लिए कर्नाटक की आकांक्षाओं को बजटीय चर्चा में जगह नहीं मिली। सीतारमण की बजटीय रणनीति के नतीजे राजकोषीय आवंटन तक ही सीमित नहीं रहकर बहुत आगे तक फैलेंगे तथा वे राज्य शासन के गलियारों में गूंजेंगे, जिससे विपक्षी नेताओं और नीति निर्माताओं के बीच आक्रोश और आशंकाएं पैदा होंगी। विपक्ष शासित राज्यों की कथित उपेक्षा मौजूदा भ्रंशरेख को और गहरा करने तथा क्षेत्रीय शिकायतों को और बढ़ाने का खतरा उत्पन्न करेंगी, जो संभावित रूप से भारत के विकास के लिए आवश्यक सहयोगी भावना को कमजोर करती है।

नीट' अब क्लीन

नीट परीक्षाओं को लेकर देशव्यापी हंगामे व राजनीतिक बयानबाजियों के बावजूद यह सुखद ही है कि देश की शीर्ष अदालत ने चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के लिये आयोजित हुई नीट परीक्षा को दुबारा कराने की मांग खारिज कर दी है। हालांकि, मंगलवार को आए फैसले का मानवीय पक्ष यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 लाख अभ्यर्थियों को होने वाली परेशानी को प्राथमिकता दी है। इसके बावजूद शीर्ष अदालत का फैसला भारत में परीक्षा प्रक्रियाओं में प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। कोर्ट के व्यावहारिक फैसले के बावजूद इस विवाद ने हमारी शैक्षिक व परीक्षा प्रणाली के भीतर व्याप्त विसंगतियों को भी उजागर किया है। बहरहाल, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की यह टिप्पणी कि लीक परीक्षा प्रणाली का उल्लंघन नहीं है, एक अस्थायी राहत जरूर प्रदान करता है। लेकिन इस सिस्टम में अंतर्निहित कमजोरियों को संबोधित किया जाना जरूरी है। इसके बावजूद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए और आईआईटी दिल्ली द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार बिहार के हजारीबाग और पटना में लीक महत्वाकांक्षी चिकित्सा पेशेवरों के लिये होने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजन के तौर–तरीकों की विश्वसनीयता पर प्रश्न तो उठाते ही हैं। प्रभावित छात्रों के मामलों को निपटाने के लिये, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी पर न्यायालय की निर्भरता समस्या के दीर्घकालीन समाधान के बजाय एक कामचलाऊ दृष्टिकोण को ही दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर गत जून माह में यूजीसी–नेट परीक्षा का रद्द होना भी चिंताओं को और बढ़ा देता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को अज्ञात सूत्रों से मिले तथ्यों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने स्वतरू संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की थी। हालांकि यह कदम छात्रों के हितों की तात्कालिक रक्षा की दृष्टि से सार्थक है लेकिन यह घटनाक्रम हमारी परीक्षातंत्र के बुनियादी ढांचे की कमजोरी को ही उजागर करता है। कह सकते हैं कि परीक्षा तंत्र की संवेदनशीलता के मद्देनजर ऐसे तदर्थवाद व पारदर्शिता की कमी छात्र समुदाय में अविश्वास व चिंता को बढ़ाते हैं। बहरहाल, हाल की ये घटनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं तथा परीक्षाएं आयोजित करने वाले तंत्र के ढांचे में व्यापक बदलाव की जरूरत को बताती हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एन.टी.ए. की संरचना की समीक्षा के लिये एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की जाएगी, निश्चित रूप से यह संस्था की विश्वसनीयता बनाये रखने की दिशा में एक उचित कदम है। हालांकि, इसके साथ ही परीक्षाओं में सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिये मजबूत उपायों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। निस्संदेह, गाहे–बगाहे होने वाले परीक्षा घोटाले न केवल शैक्षणिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं बल्कि शिक्षा और कैरियर के नाजुक मोड़ पर खड़े युवा उम्मीदवारों के भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। भारत एक युवाओं का देश है। ऐसे में अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का सदुपयोग करने के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इस घटनाक्रम के बाद सरकार को परीक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने और युवाओं की आकांक्षाओं को संबल देने के लिये इस क्षेत्र में सुधारों को वरीयता देनी चाहिए। निस्संदेह, मेडिकल प्रवेश परीक्षा के मामले के निस्तारण में सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता की सराहना की जानी चाहिए। बड़ी संख्या में याचिकाएं परीक्षा दोबारा आयोजित कराने के लिये दायर किये जाने के बावजूद, लाखों छात्रों के हित व वक्त की जरूरत के मुताबिक कोर्ट ने तार्किक फैसला दिया। जिसमें इस बात पर ध्यान दिया गया कि किसी गड़बड़ी से परीक्षा किस सीमा तक प्रभावित हुई है। कोर्ट ने इस बाबत ठोस व तार्किक पक्ष को प्राथमिकता दी। साथ ही परीक्षा के सामाजिक पक्षों को भी ध्यान में रखा। निश्चित रूप से जिन परीक्षार्थियों का चयन हो चुका था, उन्हें पुनरू परीक्षा देने को बाध्य करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। बहरहाल, इस मामले में सीबीआई द्वारा तत्परता से की गई कार्रवाई और संदिग्धों की गिरफ्तारी उन लोगों में भय पैदा करेगी, जो लंबे अर्से से परीक्षा लीक के काले धंधे में धंसे हुए थे। जाहिर है कि शासन–प्रशासन की सक्रियता, सख्ती व समय रहते कार्रवाई किसी भी क्षेत्र में शुचिता स्थापित करने में सहायक हो सकती है।

आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम एंथे-2024 के लांच की घोषणा'

कक्षा सातवीं से बारहवीं के छात्रों के लिए शत प्रतिशत फीसदी तक छात्रवृत्ति और नकद पुरस्कार की पेशकश

लखनऊ। अपनी प्रमुख छात्रवृत्ति परीक्षा एंथे के गौरवशाली 15 वर्षों को पूरा करते हुए, परीक्षण तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (एईएसएल) ने गर्व से बहुप्रतीक्षित आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम (एंथे) 2024 के लांच की घोषणा की है। एंथे लोकप्रिय और सबसे अधिक मांग वाली परीक्षा है, जो सातवीं–बारहवीं कक्षा के छात्रों को महत्वपूर्ण नकद पुरस्कारों के साथ 100 प्रतिशत तक छात्रवृत्ति अर्जित करने का मौका देती है, जिससे उन्हें चिकित्सा या इंजीनियरिंग में एक सफल करियर के अपने सपनों को हासिल करने में मदद मिलती है। इस वर्ष, इसे विशेष और रोमांचक बनाने के लिए इसमें पांच उत्कृष्ट छात्रों के लिए फ्लोरिडा, यूएसए में कैनेडी स्पेस सेंटर की पांच दिवसीय पूर्ण–खर्च–भुगतान यात्रा शामिल की गई है। फ्लोरिडा में स्थित जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर, संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) के दस फील्ड सेंटरों में से एक है। एंथे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को आकाश के व्यापक कोचिंग कार्यक्रमों से लाभ होगा, जो छात्र नीट, जेईई, राज्य सीईटी और एनटीएसई और ओलंपियाड जैसी छात्रवृत्ति परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (एईएसएल) के सीईओ और एमडी श्री दीपक मेहरोत्रा ध्ने कहा, "आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम (एंथे) ने अनगिनत छात्रों की आकांक्षाओं और क्षमताओं के बीच अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंथे के इन 15 वर्षों का जश्न मनाते हुए, हमने अपने पाठ्यक्रमों को पूरे देश में योग्य छात्रों के लिए सुलभ बनाने का काम किया है, चाहे उनका स्थान कोई भी हो। एंथे छात्रों को, चाहे वे कहीं भी हों, अपनी गति से नीट और आईआईटी–जेईई परीक्षाओं की तैयारी करने में सक्षम बनाता है। हम एंथे 2024 में मजबूत भागीदारी की आशा करते हैं और छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित हैं। इस बार एंथे अपने 15वें सफल वर्ष का जश्न मना रहा है, और इसके पास श्रेष्ठ उपलब्धियों का एक शानदार रिकॉर्ड है। इन वर्षों में, एंथे के कई छात्रों ने नीट यूजी और जेईई एडवांस्ड जैसी प्रतिष्ठात्मक परीक्षाओं में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। एंथे के माध्यम से आकाश में दाखिल होने वाले कुछ प्रमुख उपलब्धियां शामिल हैं ऋषि शेखर शुक्ला (जेईई एडवांस्ड 2024 एआईआर 25), कृष्णा साई शिशिर (जेईई एडवांस्ड 2024 एआईआर 67), अभिषेक जैन (जेईई एडवांस्ड 2024 एआईआर 78) और अन्य। नीट 2023 में हमारे शीर्ष स्कोरर्स शामिल हैं कौस्तव बौरी (एआईआर 03), ध्रुव आडवाणी (एआईआर 05), सूर्य सिद्धार्थ एन (एआईआर 06), आदित्य नीरज (एआईआर 27) और आकाश गुप्ता (एआईआर 28)। एंथे 2024 का आयोजन 19 से 27 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में, भारत के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा, 100 प्रतिशत तक की छात्रवृत्तियां के अलावा, शीर्ष स्कोरर्स को नकद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। एंथे ऑफलाइन परीक्षा 20 और 27 अक्टूबर 2024 को आकाश इंस्टीट्यूट के सभी 315 से अधिक केंद्रों पर सुबह 10रू30 बजे से 11रू30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि ऑनलाइन परीक्षा 19 से 27 अक्टूबर 2024 के बीच किसी भी समय लिया दी जा सकती है। छात्र अपने अनुकूल समय में एक घंटे का स्लॉट चुन सकते हैं। एंथे एक घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें कुल 90 अंक होंगे और 40 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो छात्रों की उनकी कक्षा और विषय विचारों के आधार पर होंगे। कक्षा 7 से 9 के छात्रों के लिए, प्रश्न भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, गणित और मेंटल एबिलिटी से संबंधित होंगे। कक्षा 10 के छात्रों के लिए चिकित्सा शिक्षा के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और मेंटल एबिलिटी से संबंधित होंगे, जबकि इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और मेंटल एबिलिटी से संबंधित होंगे। ठीक उसी तरह, नीट के लिए लक्ष्य रखने वाले कक्षा 11–12 के छात्रों के लिए प्रश्न भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी से संबंधित होंगे, जबकि इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित से संबंधित होंगे। एंथे 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन परीक्षा के प्रारंभ से तीन दिन पहले और ऑफलाइन परीक्षा के प्रारंभ से सात दिन पहले है। परीक्षा शुल्क दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के लिए 200 रूपये फीस निर्धारित की गई है। छात्र 15 अगस्त 2024 से पहले पंजीकरण शुल्क पर फ्लैट 50 प्रतिशत की छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। एंथे 2024 के परिणाम 8 नवंबर 2024 को कक्षा 10 के छात्रों के लिए, 13 नवंबर 2024 को कक्षा 7 से 9 के लिए, और 16 नवंबर 2024 को कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए घोषित किए जाएंगे। इन परिणामों को हमारी एंथे की वेबसाइट anthe.aakash.ac.in पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

बस और ट्रक में भिड़ंत, 2 की मौत,31 यात्री घायलय बचाने पहुंची एंबुलेंस हुई खराब

अलीगढ़। जनपदके अकराबाद थाना क्षेत्र में पनेठी में देर रात एक रोडवेज बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत जो गई। रोडवेज बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी और फिर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में रोडवेज बस चालक और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जबकि 31 से अधिक यात्री घायल हो गए। सूचना पर घायलों को लेने पहुंची एंबुलेंस भी खराब हो गई। इस दौरान एंबुलेंस को धक्का लेकर स्टार्ट कराया गया। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल और जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया है। अकराबाद में देर रात लगभग 12.30 बजे के आसपास यह हादसा हुआ। कानपुर के आजाद नगर डिपो की रोडवेज बस सवारियां लेकर दिल्ली की ओर जा रही थी। बस में 39 सवारियां और एक बच्चा बैठे थे। यह बस जीटी रोड होते हुए अलीगढ़ पहुंची थी। अकराबाद में जैसे ही बस जसरथ पेट्रोल पंप के सामने पहुंची, तो रोडवेज बस ने ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। अचानक वाहनों की टक्कर होने से हड़कंप मच गया और भदगड़ मच गई। वहीं बस में सवार सवाारियों के गंभीर चोटें भी आई, जिसके बाद सभी बस से बाहर निकले और मदद के लिए चीख पुकार करने लगे। रोडवेज बस के परिचालक सावल सिंह ने बताया कि रात में ड्राइवर को अचानक नींद आग गई थी और वह बस को संभाल नहीं पाया। यही कारण है कि बस ने पीछे से ट्रक में टक्कर मारी और यह हादसा हो गया। कंडक्टर ने बताया कि बस ड्राइवर नया है और वह पहली बार उसके साथ बस लेकर आया था। हादसे के बाद पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल और मेडिकल कालेज में भर्ती कराया है। वहीं इलाज के दौरान रोडवेज बस के चालक और बस में सवार एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों के परिजनों को सूचना भेजी है।अकराबाद में जिस जगह पर हादसा हुआ है, वहीं चंद कदम की दूरी पर ट्रामा सेंटर बना हुआ है। लेकिन मौके पर वहां कोई सुविधा नहीं मिली, न ही कोई डॉक्टर मिला। जिसके कारण घायलों को दूसरे अस्पताल में ले जाना पड़ा। घायलों को ले जाने के लिए जब एंबुलेंस स्टार्ट की गई, तो वह भी नहीं चली। जिससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। सीओ बरला सर्जना सिंह ने बताया कि हादसे में इलाज के दौरान बस ड्राइवर और एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं अन्य घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।

बारिश से मौसम हुआ सुहावना,लगभग एक महीने से बारिश का इंतजार कर रहे थे लोग

अलीगढ़। अलीगढ़ में पड़ रही भीषण उमस से लोगों को शुक्रवार को राहत मिली। लगभग एक महीने के इंतजार के बाद जिले में बारिश हुई और सड़कें भीग गई। हालांकि 10–15 मिनट तक हल्की बरसात होती रही और फिर शांत हो गई। लेकिन ठंडी हवाओं ने मौसम सुहावना कर दिया। जिले में जुलाई का पूरा महीना सूखा गया और लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। आसमान में बादल आते भी थे तो बिना बरसे ही लौट जा रहे थे। जिसके कारण लोग उमस भरी गर्मी का शिकार हो रहे थे और मौसम चिपचिपाहट भरा हो गया था। शुक्रवार को हल्की बरसात हुई तो लोगों को इससे राहत मिली। अलीगढ़ में पिछले माह जून में लगातार दो–तीन दिन तक बरसात हुई थी। लेकिन इसके बाद जुलाई का पूरा महीना सूखा ही बीत गया था। जिसके कारण तापमान में भी बढ़ोत्तरी हुई थी और गुरुवार को जिले का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। शुक्रवार को जब हल्की बरसात हुई और ठंडी हवाएं चली तो जहां एक ओर लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं दूसरी ओर तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को दोपहर में जिले का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। वहीं आने वाले दिनों में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है। अलीगढ़ में शुक्रवार दोपहर 1 बजे के बाद 10–15 मिनट ही हल्की बरसात हुई। इससे सड़कें भीग गई और ठंडी हवाओं से गर्मी से राहत मिली। लेकिन कुछ देर बाद जब हवा चलनी बंद हुई तो लोगों को फिर चिपचिपाहट का एहसास होना शुरू हो गया। फिलहाल आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और लोग अभी तेज बारिश का अनुमान लगा रहे हैं। अगर बारिश न हुई और धूप निकल आई तो लोगों को दुबारा से भीषण उमस का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में अलीगढ़ में अच्छी बारिश होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

14 सितम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

अवध की आवाज ब्यूरो

उन्नाव। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के अपर जिला जज/ सचिव श्री मनीष निगम द्वारा बताया गया कि जन सामान्य को त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने हेतु आगामी 14 सितम्बर 2024 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के दृष्टिगत माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव के निर्देशानुसार अपर जिला जज/सचिव श्री मनीष निगम द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में तहसील न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह–समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन पत्र देकर अन्तिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लम्बित मामले से छुटकारा पाया जा सकता है। उन्होने जानकारी देते हुए कहा कि लोक अदालत में पक्षो के मध्य आपसी सुलह–समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण पक्षकार–व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकते हैं। लोक अदालत में वाद निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लम्बित मामले के लोक अदालत में निस्तारण पर न्यायालय शुल्क वापसी की व्यवस्था है। इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। कानूनी जटिलताओ से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक/सुलह सुमझौते से निस्तारित होने वाले वाद, उत्तराधिकार से संबंधित सिविल मामले, वाद वापसी के मामले, बैंक ऋण वसूली प्री–लिटिगेशन वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले, नगर निगम/नगर पालिका अधिनियम, श्रम संबंधी वाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, राजस्व संबंधित मामले, सर्विस मैटर्स, मनरेगा वाद, व्यापार कर वाद, वजन व मापतौल अधिनियम, वन अधिनियम, उपभोक्ता फोरम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, एन0आई0एक्ट के वाद, विद्युत एवं जल संबंधी अन्य वाद, आरबीटेशन वाद, आपदा राहत वाद, यातायात चालानी वाद आदि का निस्तारण कराया जा सकता है। जनपद वासियों से अपील है कि यदि आप किसी भी लम्बित वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह–समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चहते है, तो कृपया संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के कार्यालय से सम्पर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत करा सकते है।

जनपद उन्नाव में अचलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मवेशियों का भरा ट्रक बदरका पुलिस के द्वारा पकड़ा गया

अवध की आवाज ब्यूरो

उन्नाव। अचलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर लखनऊ हाईवे स्थित यादव ढाबा के पास से मवेशियों से भरे ट्रक को बदरका चौकी प्रभारी सुब्रत तिवारी ने पकड़ा। अवध की आवाज अचलगंज कानपुर लखनऊ हाईवे पर बदरका चौकी पुलिस ने मवेशियों से भरा ट्रक को पकड़ा ट्रक के चालक व क्लीनर पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर 47 मवेशियों किसानों को सुपुर्दगी में दिया बांदा से 47 मवेशियों को लादकर ट्रक चालक दही औद्योगिक क्षेत्र स्थित स्लॉटर हाउस जा रहा था । बदरका चौकी प्रभारी ने कानपुर लखनऊ हाईवे स्थित यादव ढाबा के पास ट्रक को रुकवा लिया ट्रक में मवेशी भरे देख चालक मध्य प्रदेश के सागर निवासी फारुख खान व खलासी जबलपुर मध्य प्रदेश निवासी समीर को हिरासत में लेकर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत बदरका चौकी इंचार्ज में विधिक कार्रवाई की।

दारुल उलूम देवबंद के पूर्व शिक्षक हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद के निधन पर मदरसे में हुई शोक सभा

अवध की आवाज ब्यूरो
श्री प्रकाश गुप्ता

सीतापुर। तम्बौर सीतापुर। प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और दारुल उलूम देवबंद के पूर्व शिक्षक हजरत मौलाना मुफ्ती शकील अहमद के निधन पर गुरुवार को कस्बे के मदरसा जियाउल उलूम में शोकसभा हुई। जिसमे मदरसे के मोहतमिम मौलाना शाहिद अली ने कहा की मुफ्ती साहेब बहुत अच्छे मुकर्रर और खतीब थे। मुफ्ती मोहम्मद खबीर नदवी ने कहा की मुफ्ती साहेब के रूप में एक इल्मी और अदबी नुकसान हुआ है। दारुल उलूम जैसे शिक्षण संस्थान में बतौर शिक्षक काम करने बाद तम्बौर जैसे ग्रामीण इलाके में शैक्षिक सुधार लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा की वह अपनी तकरीर में बहुत कम समय बहुत आला बात कहने का हुनर रखते थे। ईदगाह इमाम मौलाना इदरीस ने बताया की वह कस्बे ही नही बल्कि जिले की शान थे। इसके अलावा मौलाना सुहैल नदवी, मौलाना नबीउद्दीन नदवी, मुंशी एहतिशाम, कारी मोईद, मो जियाउल हक, शेख मेराज, मौलाना कमाल अहमद आदि मौजूद रहे।

बाल श्रम से 05 किशोर कराये गये मुक्त

अवध की आवाज ब्यूरो

उन्नाव। थाना ए.एच.टी,जनपद उन्नाव राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय बाल बचाव एवं पुनर्वास, किशोर श्रम उन्मूलन हेतु संचालित अभियान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के आदेशानुसार व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) उन्नाव के मार्गदर्शन में चलाये जा रहे अभियान के संबंध में थाना ए०एच०टी० एवं बाल श्रम आयुक्त की संयुक्त टीम आदि द्वारा थाना क्षेत्र कोतवाली सदर, अचलगंज व गंगाघाट के प्रमुख मार्गों पर पड़ने वाले बाजारों/प्रतिष्ठानों व ढाबों रेलवे स्टेशन आदि पर बाल श्रम रेस्क्यू चेकिंग अभियान चलाया गया। 15 प्रतिष्ठानों को चेक किया गया जिसमें दौराने चेकिंग 05 प्रतिष्ठानों मे 18 वर्ष से कम आयु के 05 बालकों को बाल श्रम करते हुये रेस्क्यू किया गया । जिसके संबंध में मौके पर ही सम्बन्धित प्रतिष्ठान मालिकों को श्रम आयुक्त विभाग की टीम द्वारा नोटिस देकर विधिक कार्यवाही करते हुये रेस्क्यू किये गये बालकों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया । इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान/ढाबा मालिको को बालश्रम न कराने के संबंध में एवं मेडिकल स्टोर मालिकों को नशीली दवा आदि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ना देने हेतु बताया गया तथा प्रतिष्ठान मालिको को प्रतिष्ठान में सी०सी०टी०वी० कैमरा लगवाने हेतु अनुरोध किया गया। अभियान के संबंध में विशेष जानकारी दी गयी व बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग बच्चे से कार्य कराते हुये पाया जाता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त मुख्य चौराहों व तिराहों पर आने जाने वाले व्यक्तियों को एकत्रित कर नाबालिग बच्चों के संबंध में होने वाले अपराधों की जानकारी देते हुये आम जनमानस को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कार्य न कराने के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा आम जनमानस को इमरजेंसी सहायता हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 108, 112, 1090, 1098, 1076, 181 आदि के संबंध में जानकारी दी गई।

दबंगो ने पड़ोसी की मेढ़ खोदकर लगा दी यूके लिप्टस की पौध।

अवध की आवाज ब्यूरो
श्री प्रकाश गुप्ता

सीतापुर। मिश्रित सीतापुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर मजरा हुमांयूपुर निवासिनी रामरानी पत्नी रामकृपाल ने प्रभारी निरीक्षक को एक सिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है। कि गांव के ही निवासी जमुना व विशुनदयाल पुत्र गण सहदेव ने कस्बा मिश्रित के मोहल्ला रन्नुपुर निवासी सरवन पुत्र रामरतन का खेत बटाई पर लिया है। उसी से लगे हुए पीड़िता के खेत है। बटाईदारो ने पीड़िता के दोनों खेतो की मेढ़ खोद कर यूके लिप्टस के पौधे लगा दिए है। पीड़िता का आरोप है। कि आज जब वह अपने पति के साथ खेत देखने गई। तो आरोपियों से मेढ़ खोदने का बिरोध किया। जिस पर दोनों आरोपी एक राय होकर जान माल की धमकी देते हुए आमांदा फौजदारी हो गए। इस लिए पीड़ित महिला ने मांमले का सिकायती पत्र प्रभारी निरीक्षक को देकर आरोपियों के बिरुध्द कार्यवाही करने की मांग की है।

ग्राम पंचायत जसरथपुर में तैनात ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम प्रधान बने भ्रष्टाचार का पर्याय।

अवध की आवाज ब्यूरो
श्री प्रकाश गुप्ता

सीतापुर। मिश्रित सीतापुर / विकासखंड मिश्रित की घोटालों में चर्चित चल रही ग्राम पंचायत जसरथपुर के नित नए घोटाले खुलकर सामने आ रहे है । ग्राम पंचायत जसरथपुर में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी धीरेन्द्र कुमार नंद इसी ब्लाक की ग्राम पंचायत कादीनगर के निवासी है। फिर भी खादी के संरक्षण में विकासखंड मिश्रित में ही अपनी नौकरी पूरी कर रहे है। अभी बीते दिनों मजरा फुलवारी निवासी एक महिला ने प्रदेश शासन सहित अन्य कई अधिकारियों से लिखित सिकायत की थी। उसके आवास की मजदूरी गोविंद पुत्र शंकर नामक व्यक्ति के खाते पर भेज कर निकाल ली गई है। ग्राम पंचायत अधिकारी धीरेन्द्र कुमार नंद व प्रधान रामपाल व्दारा किए गए भ्रष्टाचार के तमांम मांमले खुलकर सामने आ रहे है। फिर भी जनपद के जिम्मेदार अधिकारी जांच और कार्यवाही करना मुनासिब नही समझ रहे है। आपको बता दे कि ग्राम पंचायत जसरथपुर में ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान व्दारा किसी देवेन्द्र कुमार व्यक्ति के नाम दिनांक 26 दिसम्बर 2023 को टेन्डर प्रकाशन के नाम पर नियम बिपरीत एक ही दिन में चार बार 5 हजार 250 रुपए की धनराशि भेजी गई है। जानकार सूत्र बताते है। कि देवेन्द्र कुमार के पास जनपद सीतापुर से प्रकाशित होने वाला प्रतिपल संवाद समांचार पत्र है। उसमें इतना महंगा बिल कैसे हो सकता है। जब कि प्रदेश शासन के निर्देशानुसार किसी राष्ट्रीय स्तर के समांचार पत्र में टेंडर प्रकाशन कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए है। फिर भी पंचायत सचिव व प्रधान व्दारा जनपद से प्रकाशित होने वाले समांचार पत्र के स्थानीय प्रतिनिधि से सांठ गांठ करके 5 सौ रुपए में टेन्डर का प्रकाशन कराकर सरकारी धनराशि का खुले आम गमन किया जा रहा है। जिसकी तरफ जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को जांच कराकर कार्यवाही करने की आवस्यक्ता है।

जिलाधिकारी ने फरियादियों की सुनवाई कर संबंधित विभागो को समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के दिए निर्देश

अवध की आवाज ब्यूरा

सीतापुर। सीतापुर श्री प्रकाश गुप्ता आज जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने फरियादियों की सुनवाई गंभीरता से सुनकर संबंधित विभागाध्यक्ष को दूरभाष से निर्देश दिया कि फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारित करें। जिलाधिकारी महोदय ने विभिन्न अधिकारियों को कड़े निर्देश दिया कि आई0जी0आर0 एस0 को प्राथमिकता पर निस्तारित करे, निस्तारण में देरी व लापरवाही क्षम्य नही होगी, आई0जी0आर0 एस0 डिफाल्टर होने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिलाधिकारी महोदय ने भूमि विवाद, दाखिल खारिज से संबंधित शिकायतों को ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए। समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि पेंशन व लाभार्थीपरक योजनाओं को लाभार्थियों को बिना विलंब के पहुंचाई जाये। पेंशन आदि से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से निस्तारण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी महोदय ने विवाद से संबंधित शिकायतों को पुलिस विभाग को अंतरित कर निस्तारित करने के सख्त निर्देश प्रदान किया।

जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भंडार कच्छ का किया निरीक्षण

अवध की आवाज ब्यूरो

सीतापुर। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने आज इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन भण्डारण कक्ष एवं वी0वी0 पैट भण्डारण कक्ष (वेयर हाउस का वाह्य निरीक्षण) का मासिक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं एवं आवश्यक दिशा–निर्देश संबंधित को दिये। उन्होंने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन भण्डारण कक्ष में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे की जांच टी0वी0 स्क्रीन पर देखी एवं साफ–सफाई के निर्देश भी दिये। इस दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं निर्वाचन विभाग कर्मचारी उपस्थित रहे।

गांव के दबंगो ने चक मार्ग पर कि अवैध कब्जा

अवध की आवाज ब्यूरा
श्री प्रकाश गुप्ता

सीतापुर। मिश्रित सीतापुर /कोतवाली क्षेत्र के ग्राम फुलरुवा निवासी अंकित कुमार पुत्र बिंदेश्वर ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है। कि गांव में सार्वजनिक चक मार्ग गाटा संख्या 34 रकबा 0.040 हेक्टेयर स्थित है। गांव के ही निवासी श्रीकांत , उमाकांत पुत्र गण नरेश प्रसाद, प्रतीक पुत्र श्रीकांत, दिव्यांश पुत्र उमाकांत ने उपरोक्त चक मार्क को जोतकर अपने खेतों में मिल लिया था। जिससे अन्य किसानों का रास्ता बंद हो गया था। सभी किसानों ने उपजिलाधिकारी से शिकायत करके चक मार्ग को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की थी। उपजिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर चक मार्ग कब्जा मुक्त कराकर ग्राम प्रधान को कच्ची सड़क पटाने का निर्देश दिया था। जिससे ग्राम प्रधान ने उपरोक्त चक मार्क पर कच्ची सड़क का पटान भी करा दिया था। परंतु आरोपी इतने दबंग हैं। कि उन्होंने कच्ची सड़क को पुनः जोत कर अपने खेतों में मिला लिया है। जिससे पड़ोसी किसानों का आम रास्ता फिर से बंद हो गया है। पड़ोसी किसान जब इस बात का विरोध करते हैं। तो आरोपी जान माल की धमकी देते हुए आमांदा फौजदारी हो जाते हैं। इस लिए पीड़ित व्यक्ति ने मांमले का शिकायती पत्र जिलाधिकारी को देकर अवरुद्ध चक मार्ग को पुनः कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की हैं।

’लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए जागरूकता और सहभागिता जरूरी है’ : रुचिता चौधरी

लखनऊ। लैंगिक हिंसा को अस्वीकार्य बनाने वाले संगठन ब्रेकथ्रू ने आज लखनऊ में एक कार्यक्रम में अपने महिला सुरक्षा ऑडिट के परिणाम जारी किए। ब्रेकथ्रू का सुरक्षा ऑडिट मॉडल असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करता है और सुरक्षित सार्वजनिक स्थान बनाने की योजना बनाता है। लखनऊ में चार समुदायों में लागू की गई, रिपोर्ट ने महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक सुरक्षा मुद्दों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को भारत में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक माना जाता है। यह न केवल देश पर एक बड़ी आर्थिक लागत लगता है बल्कि महिलाओं और लड़कियों को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से भी रोकता है। ब्रेकथ्रू महिलाओं और लड़कियों के बीच आकांक्षा, नेतृत्व, एजेंसी और बातचीत कौशल को बढ़ावा देकर लिंग–समान संस्कृति की ओर एक पीढ़ीगत बदलाव को सक्षम बनाता है। महिला सुरक्षा ऑडिट लखनऊ में गरीब आवास योजना दुबग्गा,पारा, लौलाई और बरवानकलां नामक चार स्थानों पर आयोजित किया गया था और इसे कम्युनिटी यूथ लेड इनिशिएटिव द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में मौजूद महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की पुलिस अधीक्षक रुचिता चौधरी ने कहा “सुरक्षा ऑडिट के माध्यम से निष्कर्ष बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण और योग्य कदम है। इसकी सिफारिशें उल्लेखनीय हैं और इन्हें निश्चित रूप से प्रशासन का समर्थन मिलना चाहिए। मैं लोगों से आग्रह करूंगी कि वो सामने आ कर और निडर होकर रिपोर्ट करें। हम महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं सभी को हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करने और उसका सही तरीके से उपयोग करने की भी सलाह दूँगी।” ब्रेकथ्रू की चीफ प्रोग्राम ऑफिसर नयना चौधरी ने बताया कि ष्महिला सुरक्षा ऑडिट के परिणामों की रिपोर्ट हमारे सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के व्यापक मुद्दे को समझने और संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ से एकत्र की गई अंतर्दृष्टि से बेहतर बुनियादी ढांचे, बेहतर मार्ग प्रकाश व्यवस्था और अधिक प्रभावी पुलिसिंग की तत्काल आवश्यकता का पता चलता है। लेकिन इन उपायों से परे, हमें लैंगिक समानता और सुरक्षा के प्रति हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण में सामूहिक बदलाव की आवश्यकता है। ब्रेकथ्रू इस बदलाव को आगे बढ़ाने और हिंसा और भेदभाव से मुक्त भविष्य की ओर अग्रसर होने में हमारे युवाओं का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।सेफ्टी ऑडिट की सिफारिशों का उद्देश्य बुनियादी ढांचे में सुधार, सामुदायिक जुड़ाव, बढ़ी हुई निगरानी और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है। इन सिफारिशों को लागू करना एक सहायक वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है जहां महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित महसूस कर सकें।निष्कर्षों के आधार पर लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा के व्यापक मुद्दे का समाधान करने के लिए व्यापक सुरक्षा उपायों और सामुदायिक भागीदारी की सिफारिश की जाती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण करना जरूरी है। पीड़ितों की प्रभावी ढंग से मदद देने के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम उन्हें आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करते हैं।महिला सुरक्षा ऑडिट के परिणाम और सिफारिशें सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्यापक और सहयोगात्मक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, अपर्याप्त निगरानी और सामुदायिक भागीदारी की कमी जैसे मुद्दों को संबोधित करने से एक सुरक्षित वातावरण तैयार होगा जो महिलाओं और लड़कियों को सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सशक्त बनाएगा। इस अवसर पर समुदाय के युवाओं ने लखनऊ नगर निगम के प्रतिनिधि ा को एक माँग पत्र दिया।

चला बुलडोजर,3 हजार वर्गमीटर जमीन कराई कब्जा मुक्त, 15 करोड़ कीमत

नोएडा। प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण को हटाने का अभियान लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह प्राधिकरण की टीम ने सेक्टर–44 में अभियान चलाकर करीब 3 हजार वर्गमीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। जमीन के चारो ओर बाउंडरी वॉल बनाकर कब्जा किया जा रहा था। ये जमीन प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2031 में शामिल है। ये जमीन आवासीय श्रेणी में आती है। प्राधिकरण अधिकारी ने बताया कि नोएडा के सेक्टर–44 के सदरपुर गांव में करीब 3 हजार वर्गमीटर जमीन प्राधिकरण अधि ासूचित और कब्जा प्राप्त जमीन है। भू माफियाओं ने इस जमीन के चारो ओर बाउंडरी करवाकर गेट लगा दिया था। प्राधिकरण को जानकारी मिली। नियमानुसार पहले नोटिस जारी किया गया कि इसे तत्काल हटा लिया जाए। अन्यथा प्राधिकरण इस बाउंडरी को ध्वस्त कर देगा। ऐसे में शुक्रवार सुबह प्राधिकरण 50 लोगों की टीम और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। जब तक अतिक्रमण कर्ता कुछ समझता प्राधिकरण ने बाउंडरी वॉल और गेट को तोड़ते हुए जमीन पर कब्जा कर लिया। इस जमीन की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आकी जा रही है। बता दे नोएडा प्राधिकरण 2020 से अब तक करीब 5 लाख वर्गमीटर जमीन को कब्जा मुक्त करा चुकी है। इसकी कीमत करीब 2 हजार करोड़ रुपए के आसपास है।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव से छात्राओं को जागरूक किया

लखनऊ। राजधानी के आलमबाग स्थित गुरुनानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की जानकारी दी गई। इस मौके पर विशेषज्ञों ने बताया कि इस बीमारी से सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को होती है। इसके रोकथाम के लिए लगने वाली वैक्सीन के बारे में जानकारी सभी छात्राओं में साझा की गई। इस दौरान स्त्री रोग और कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्या गुप्ता ने बताया कि सजगता से कैंसर से बचाव संभव है। उन्होंने छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा कि अगर समय पर वैक्सीन लगवा दी जाए तो कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने नियमित व्यायाम करने की भी सलाह दी। कार्यक्रम का संचालन अजंता हॉस्पिटल के चीफ जनरल मैनेजर केएस ऐबॉट ने किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्या मंजीत कौर ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

अवध की आवाज ब्यूरो

पत्रकार सुरक्षा महासमिति की मासिक बैठक में पत्रकार सुरक्षा महा समिति के पदाधिकारी ने पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान के लिए गंभीरता से विचार करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान के लिए पुलिस महानिदेशक और जिले के सभी एसपी और कमिश्नर को इस बाबत सभी जनपदों में पत्रकार सुरक्षा महासमिति के जिला अध्यक्ष अपनी टीम के साथ जगह–जगह उपस्थित होकर पत्रकारों की पीड़ा को संबंधित अधिकारियों को अवगत कराये।

पत्रकारों की सुरक्षा एवं उनके हितों का पूरा ध्यान रखते हुए पत्रकारों का सम्मान करने के साथ थी उनके साथ होने वाली किसी भी घटना का तुरंत कार्रवाई के लिए जनपद के पत्रकार सुरक्षा महासमिति के अध्यक्ष वार्ता करके कार्रवाई कराना अपना प्रथम दायित्व समझे। पत्रकार सुरक्षा महासमिति की मासिक बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने पत्रकारों को सुझाव देते हुए कहा पत्रकारों को किसी भी विचारधारा से प्रभावित होकर खबर का प्रकाशन प्रसारण नहीं करना चाहिए। पत्रकार को हर समय न्यायनिष्ठ और निष्पक्ष रहना चाहिए। और सारी जानकारी उसके पास होनी चाहिए खबर की मूल आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खबर जो है ठीक वैसे ही पेश करना चाहिए। समाचारों में तत्वों को तोड़ा मरोड़ा न जाए न कोई सूचना छिपाई जाए। किसी के सम्मान को ठेस न पहुंचे। पत्रकार अपने पद और पहुंच का उपयोग गैर पत्रकारयी कार्यो के लिए न करें। पत्रकारिता की मर्यादा का ध्यान रखते हुए पत्रकार को समाचार छापना या न छापना अवांछनीय अमर्यादित और अनैतिक है। पत्रकारिता की पगडंडी पर चलकर नियमानुसार खबर कवरेज करके सत्य का उजागर करें।

आयुष अस्पताल में चोरी, पीजीआई थाना क्षेत्र में जनरेटर की बैटरी चोरी

लखनऊ। लखनऊ के पीजीआई कोतवाली क्षेत्र के कल्ली पश्चिम में स्थित 50 बेड आयुष चिकित्सालय में चोरी हो गई। अस्पताल परिसर के अंदर दो डॉक्टरों के कमरे में लगी एसी के आउटडोर सहित जनरेटर का बैट्री तक चोर उठा ले गए। घटना की जानकारी सुबह अस्पताल पहुंचने पर हुई। जब डॉक्टरों ने कमरे में बैठकर एसी चलाई तब उन्हें चोरी की जानकारी हुई। पुलिस ने चिकित्सा अधीक्षक की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अस्पताल के चिकित्सा अध ाीक्षक संदीप कुमार शुक्ला ने बताया कि 50 बेड के आयुष चिकित्सालय में चोरी हुई है, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि चोर पीछे की बाउंड्री वॉल से अंदर घुसे और चोरी की वारदात कर भाग निकले। इंस्पेक्टर पीजीआई बृजेश चन्द्र तिवारी ने बताया कि अस्पताल के सीएमएस की तहरीर पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

कारगिल विजय दिवस पर 26 शहीदों के परिजनों और जवानों को मिला सम्मान

नोएडा। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर गौतम बुद्ध नगर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहां पर जिलाधिकारी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान जिले से 26 शहीदों के परिजन और जवानों को उनके द्वारा सम्मान दिया गया। इस तरह का कार्यक्रम पहली बार किसी जिले में आयोजित किया गया है। गौतमबुद्ध नगर के जिला कलेक्ट्रेट पर कारगिल विजय दिवस को लेकर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा और कर्नल शैलेंद्र सिंह के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहीदों के परिवार वालों को आमंत्रित किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि कारगिल विजय दिवस को भुलाया नहीं जा सकता। हमारे देश के शूरवीरों ने जिस साहस और शौर्य का परिचय दिया था। उस पर हमें गर्व होता है और हमें उन शूरवीरों के परिवार वालों का सम्मान करने का अवसर मिला। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया आज 26 शहीदों के परिजन और उन जवानों को सम्मानित किया, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया। इस दौरान पांच महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। यह वह महिलाएं थीं, जिनके पतियों ने देश के लिए लड़ते हुए शहादत दी थी। इस दौरान कर्नल शैलेंद्र सिंह ने कहा कि कारगिल में जो लड़ाई लड़ी गई थी, वह दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई थी और भारत के सैनिको ने इतनी ऊंचाई पर जाकर लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को जीता भी, जो दिखाता है कि हमारे देश के सैनिक अपने देश के लिए किस कदर तक जा सकते हैं और अपनी भारत मां की रक्षा किसी भी हालत में कर सकते हैं।

पत्रकार सुरक्षा महा समिति के द्वारा जाजमऊ चौकी इंचार्ज के उत्कृष्ट कार्य पर समिति के द्वारा सम्मानित किया गया

जाजमऊ पर पत्रकार सुरक्षा महा समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष गुड्डू मिश्रा कई पदाधिकारीयों के साथ उपस्थित होकर चौकी इंचार्ज जाजमऊ के उत्कृष्ट कार्य पर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। पत्रकार सुरक्षा महासमिति के प्रदेश उपाध्यक्ष गुड्डू मिश्रा ने चौकी इंचार्ज जाजमऊ से वार्ता दौरान कहा की क्षेत्रीय जनता पुलिस से अपेक्षा करती है कि वह अपराध को रोकें तत्काल खतरे में पड़े लोगों की मदद करें अपराधों की जांच करें अपराधियों को पकड़े सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखें तथा विशेष कर कमजोर लोगों को नुकसान से बचाए। साथ ही साथ आपसी विश्वास के मजबूत रिश्ते सार्वजनिक सुरक्षा और प्रभावी पुलिसिंग को बनाए रखे। आए हुए फरियादियों की बात को सुने क्षेत्र में जुआ सट्टा अवैध जमीन पर हो रहे कब्जा दबे कुचलों को दबाने वाले लोगों पर विधिक कार्रवाई हो। चौकी इंचार्ज के द्वारा पूर्ण भरोसा दिया गया लोगों को न्याय दिलाना प्रथम प्राथमिकता होगी।

गुड्डू मिश्रा ,प्रदेशउपाध्यक्ष

सावन जिंदगी और प्रकृति के बीच लाता है संतुलन

धरती परछाई हरियाली और आसमान में मेघमालाओं के बीच श्रावणी संस्कार एवं संकल्प बनकर बरस रही है। बारह महीनों में सावन का महीना कुछ विशेष है। धरती और सूर्य के खगोलीय संबंध पृथ्वी में पडने वाले अंतर ग्रहीय प्रभाव इस महीने को कई विशेषताओं से अलंकृत करते हैं सावन महीना प्रकृति को समृद्ध बनता है। सावन शब्द सुनते ही मन में एक अलबेली उमंग का भाव जग जाता है, सावन प्रकृति का सिंगर है प्रेम का भाव है तीज त्यौहार का चाव है। सावन में लालित्य है हरीतिमा का निखार और प्रेम का विस्तार है सावन आते ही हम सब के भीतर उमंग उत्साह उल्लास और संगीत मुखर हो जाता है। चहुंओर हरियाली बागों में पड़े झूले आकाश पर छाए काले काले मेघ और लहलहाते धान के खेत ऐसे लगते हैं मानो धरती ने धानी चुनरिया ओढ़ ली हो। रिमझिम बारिश में मिट्टी की शोधी खुशबू में लिपटी गीली हवा मैं पपीहा की टेर झींगुर की आवाज और गिरती बूंदे वातावरण में एक अलग ध्वनि उत्पन्न करती है। प्रकृति के आंगन का यह मनभावन दृश्य देखकर मन बर बस ही मधुर गान गा उठता है।

पत्रकार सुरक्षा महासमिति
गुड्डू मिश्रा
प्रदेश उपाध्यक्ष

बीबीएयू में नैक की रीजनल कांफ्रेंस,

प्रो.अनिल सहस्त्रबुद्धे बोले– 90: संस्थानों को एक्रेडिशन दिलाना लक्ष्य, 8 राज्यों के एक्सपर्ट हुए शामिल

लखनऊ। लखनऊ के बाबा साहब भीमराव आंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में शुक्रवार को नैक की रीजनल कांफ्रेंस हुई। इस कांफ्रेंस में उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के 8 राज्यों के एक्सपर्ट्स शामिल हुए। नैक कमेटी के चेयरमैन डॉ. अनिल सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि 29 जुलाई 2020 को सरकार ने एनईपी की मान्यता दी थी। आज 4 साल हो रहे हैं। यहां आने पर बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर सभी को विशेष अनुभूति हुई है। एनईपी में नवाचार, संशोधन के साथ नेशनल ही नही ग्लोबल लेवल के गोल्स पर हम फोकस कर रहे हैं। वैल्यू बेस एजुकेशन बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली, मुंबई के अलावा लखनऊ जैसे शहरों में भी पॉल्युशन ज्यादा है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि डेवलपमेन्ट के साथ वातावरण भी शुद्ध रहे। स्कूली शिक्षा से लेकर वैल्यू बेस्ड शिक्षा पर जोर है। नैक इवैल्यूएशन से पहले इनपुट बेस एजुकेशन पर ज्यादा जोर था। ये जरूरी है, पर केवल इस बात जोर देने की बात कह कर क्वालिटी पर फोकस को कम कर देते हैं। एक्रेडिशन एक माध्यम हैं, जिससे हम एजुकेशनल संस्थान की कमियों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन लेने के लिए भी घर परिवार में अक्रेडिशन की चर्चा हो। अब 8 पॉइंट ग्रेड सिस्टम, सी से लेकर ए के बीच ग्रेड दिए जा रहे हैं। करीब 65: विश्वविद्यालय अभी तक एक्रेडिशन के लिए सामने नही आ रहे हैं। वहीं 50 हजार डिग्री कॉलेजों में से 10 से 11 हजार डिग्री कॉलेज ही एक्रेडिशन के लिए सामने आए हैं। दुनिया में सिर्फ एक्रेडिशन या नॉट एक्रेडिशन का सिस्टम हैं। सिर्फ भारत मे भी ही एक्रेडिशन में ये ग्रेड सिस्टम लागू है। डॉ. राधाकृष्णन कमेटी ने सुधार करते हुए बिनारी एक्रेडिशन की बात कही। अब इसे लागू किया जा रहा है। ये भी हो सकता हैं कि पहली बार सभी को एक्रेडिशन नहीं मिलेगा। नैक भी इसको लेकर मेंटरिंग करेगा। 5 साल के अंदर 90: शिक्षण संस्थानों को अक्रेडिशन पाने पर जोर दिया हैं। यही कारण हैं कि अब हमारा फोकस बिनारी अक्रेडिशन पर हैं। इकोनॉमी के मामले में 2014 में 11–12 वें नंबर में थे, अब हम 5वें नंबर पर आ चुके हैं। अगले एक साल के भीतर हम दुनियाभर में तीसरी इकोनॉमी पर होंगे। नेशनल इंस्टिट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के जरिए कौन सा संस्थान कितना बेहतर इसे जाना जा सकेगा। लेवल 5 सबसे टॉप लेवल हैं, (इंटरनेशनल लेवल की मल्टी डिसपलीनरी यूनिवर्सिटी के लेवल का होगा, जिसमे एमआईटी, लेवल 4– इंडिया लेवल का होगा,लेवल 1– सबसे नीचे दर्जा का आप एक्रेडिशन के रूप में एक्सपर्ट और चेयरमैन के रूप में भी शामिल हो सकते हैं। यही कारण हैं कि ये कंसल्टेटिव वर्कशॉप रखी गई है। जिसको पहले से एक्रेडिशन ग्रेड मिल गया है। उसकी जब तक वैलिडिटी है, उन्हें बिनारी एक्रेडिशन में आने की जरूरत नही है। जिनका एक्रेडिशन समाप्त हो गया, उनको यहां आना पड़ेगा। जिन्होंने आज तक एक्रेडिशन नहीं लिया, उन्हें अगले एक महीने बाद जरूर से जरूर इसके लिए आगे आना पड़ेगा।

बिजली के खंभे में उतरा करंट,दो गायों की मौत

लखनऊ। राजधानी के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के स्कूटर इंडिया चौराहे के पास शुक्रवार की सुबह में विद्युत विभाग व नगर निगम की घोर लापरवाही के कारण से दो गायों की करंट लगने से मौत हो गई। पूरा मामला स्कूटर इंडिया चौराहे के पास का है। जहां बिजली के खंभे में करंट उतरने के कारण से दो गायों की मौत हुई। मौके पर मौजूद लोगों नाराजगी जताई और कहा कि नगर निगम अगर अपना काम सही से करता तो इन बेजुबान गायों की मौत ना होती। लोगों का कहना है कि चौराहे के पास नाले के किनारे लगे बिजली का खंभा जर्जर था लेकिन इसे नहीं बदला गया।

डीएम ने एआरटीओ ऑफिस का किया निरीक्षण, परिसर मे गंदगी देख जताई नाराजगी

नोएडा। डीएम मनीष वर्मा और डीसीपी राम बदन सिंह शुक्रवार दोपहर में अचानक एआरटीओ ऑफिस और रजिस्ट्री विभाग पहुंच गए। ये देख वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल डीएम को शिकायत मिली थी कि एआरटीओ विभाग में दलालों द्वारा काम कराया जा रहा है। डीएम ने यहां आए लोगों से बातचीत की। इसके बाद काउंटर पर जाकर काम कर रहे कर्मचारियों और लाइन में लगे लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि यहां पर समय से काम हो रहा है। हालांकि कुछ एक जगह विलंब होने पर लोगों को परेशानी हो रही थी। ऐसे में डीएम ने एआरटीओ सिया राम को निर्देशित किया कि किसी प्रकार से आम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां लर्निंग लाइसेंस सेंटर पर भी गए। कई फाइलों को देखा। लोगों को लाइसेंस बनवाने के लिए जो स्लॉट मिला था उस हिसाब से काम हो रहा था कि नही ये भी देखा गया। इस दौरान उन्होंने पार्किंग में वाहनों की व्यवस्थित तरीके से खड़ा करने के लिए भी कहा। इसके बाद दोनों अधिकारी रजिस्ट्री विभाग गए। यहां रजिस्ट्री कराने आए लोगों से बातचीत की। साथ ही उनसे भी दलाल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी नियम के विरुद्ध काम करे तो उसकी शिकायत की जाए। इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। निबंधन विभाग में फैली गंदगी को देखकर निर्देश दिए कि यहां तत्काल साफ–सफाई कराई जाए। यहां आम लोगों से लेकर खास सभी आते है। परिसर को साफ सुथरा रखना हमारा काम है। इसके बाद अधि ाकारियों और कर्मचारियों की वर्किंग शैली को देखा। दोनों ही अधि ाकारी करीब एक घंटे तक एआरटीओ और रजिस्ट्री विभाग में रुके।

कांवड़ यात्रा के लिए रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाई,

नोएडा डिपो से 60 बसें हरिद्वार–ऋषिकेश के लिए रिजर्व, आज से डायवर्जन लागू

नोएडा। कांवड़ यात्रा में यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए रोडवेज और परिवहन निगम ने बसों की संख्या में बढ़ोतरी की है। ये बस नोएडा से हरिद्वार, ऋषिकेश की तरफ जा रही है। परिवहन निगम ने 60 बसों की फ्लीट को कांवड़ यात्रियों के लिए लगाया गया है। जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा। वहीं कांवड़ शिविर के पास से यातायात रूट को बंद किया गया है। नोएडा बस डिपो के एआरएम एनपी सिंह ने बताया कि शहर में पिछले चार दिन में लगातार कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। सामान्य दिनों में नोएडा से उत्तराखंड के लिए आठ बस जाती थी। कांवड़ यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पिछले दस दिनों बस की संख्या को बढ़ाया गया है। इस समय कुल 60 बस उत्तराखंड जा रही हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर रूट डायवर्जन किया गया है। बस को अपने गंतव्य तक जाने के लिए लंबे रास्तों से होकर जाना पड़ा रहा है। ऐसे में रोडवेज बस के किराये में बढ़ोतरी हो गई है। ये बढ़ोतरी मेरठ, हरिद्वार और ऋषि केश जाने वाली बसों के किराए में की गई है। रूट डायवर्जन होने से किराये में 20–30 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। पांच अगस्त को डायवर्जन खत्म होने के बाद पहले वाला किराया लागू कर दिया जाएगा। सेक्टर 14ए स्थित शनि मंदिर के पास बने कांवड़ शिविर को आज से शुरू कर दिया गया। इसका संचालन शनि शक्तिपीठ बीते 13 सालों से लगातार करता आ रहा है। इस बार 1000 कावड़ियों के लिए विश्राम की व्यवस्था की गई है। मेडिकल सुविधा के साथ 24 घंटे खाने–पीने की व्यवस्था रहेगी। नोएडा से कालिंदी कुंज जाने वाले मार्ग की एक लेन आज से माल वाहक वाहनों के लिए बंद रहेगी। साथ ही, चिल्ला लाल बत्ती से ओखला पक्षी विहार के प्रवेश द्वार तक सभी तरह के वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ यात्रा के चलते यह निर्णय लिया गया है। डीसीपी ट्रैफिक यमुना प्रसाद ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। लोगों से अपील है कि डायवर्जन का पालन करें। चिल्ला लालबत्ती से ओखला पक्षी विहार गेट तक मार्ग पर वाहनों का आवाजाही पूर्णतःरू प्रतिबंधित किया गया है।

एएमयू और विंडसर मशीन्स लिमिटेड के बीच माइक्रोपोरस पॉलीमर प्रोसेसिंग के क्षेत्र में संयुक्त शोध परियोजना के लिए समझौता

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने विंडसर मशीन्स लिमिटेड, अहमदाबाद के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) और नॉन–डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (एनडीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते थर्मोप्लास्टिक्स के माइक्रोपोरस प्रसंस्करण में ‘मेड इन इंडिया’ तकनीक विकसित करने पर केंद्रित एक संयुक्त शोध परियोजना की स्थापना पर आधारित हैं। एएमयू के रजिस्ट्रार मोहम्मद इमरान, आईपीएस और विंडसर मशीन्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक और सीईओ विनय बंसोड़ ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए।एएमयू में आयोजित हस्ताक्षर समारोह में एएमयू की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकाय के डीन प्रोफेसर सालिम बेग, रजिस्ट्रार मोहम्मद इमरान, पेट्रोलियम अध्ययन विभाग की अध यक्ष डॉ. नजम सरदार और पेट्रोलियम अध्ययन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और परियोजना के प्रमुख अन्वेषक डॉ. सैयद जावेद अहमद रिजवी मौजूद रहे।विंडसर मशीन्स लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कंपनी के ईडी और सीईओ श्री विनय बंसोड़ तथा डीजीएम सुस्मित पटेल ने किया। कार्यक्रम के दौरान श्री बंसोड़ ने एएमयू परिसर तथा इसकी विविध शैक्षणिक उत्कृष्टता की प्रशंसा की। उन्होंने पॉलिमर प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में एएमयू, विशेष रूप से पेट्रोलियम अध्ययन विभाग की शोध ा क्षमताओं की सराहना की। माइक्रोपोरस प्रसंस्करण में डॉ. रिजवी की विशेषज्ञता पर प्रकाश डालते हुए श्री बंसोड़ ने डॉ. रिजवी के नेतृत्व में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और व्यावसायीकरण में विंडसर के विश्वास को व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण में इस उद्योग–अकादमिक सहयोग के पारस्परिक फायदों पर जोर दिया।अमुवि कुलपति प्रो. नईमा खातून ने कहा कि विंडसर मशीन्स ने विश्वविद्यालय की शोध ा क्षमता को पहचानते हुए इस वर्ष की शुरुआत में संयुक्त शोध ा परियोजना का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने परियोजना के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया तथा इस महत्वपूर्ण सहयोग में डॉ. नजम सरदार और डॉ. रिजवी को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी।प्रो. सालिम बेग ने उद्योग–प्रासंगिक शोध को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया तथा प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाने वाली पहलों के लिए सहयोग को प्रोत्साहित किया। मोहम्मद इमरान ने परियोजना की सफलता पर विश्वास व्यक्त करते हुए संयुक्त स्वामित्व वाली बौद्धिक संपदा के वैश्विक व्यावसायीकरण के विचार को आगे बढ़ने के महत्व को उजागर किया।डॉ. नजम सरदार ने विंडसर मशीन्स प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और परियोजना की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

अवध की आवाज हिन्दी दैनिक, प्रकाशक ,मुद्रक व स्वामी,अनिल कुमार सिंह द्वारा स्काई लाइन प्रिन्टर्स,119/23 खन्दारी लेन, लालबाग, लखनऊ उ0प्र0 से मुद्रित तथा डी–97/3 व 7,सेक्टर–7, इन्दिरा नगर,लखनऊ,उ0प्र0 से प्रकाशित। सम्पादक अनिल कुमार सिंह फोन : 0522–4340954
मो0–7905407289, Email: avadhkiaawaz@gmail.com
R.N.I.- UPHIN/2012/45127
नोट : समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादोंका न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।